सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh
RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number : F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 171, नई दिल्ली । शनिवार, 31 अगस्त 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

जीवन हमेशा अपने सबसे अच्छे रूप में आने से पहले किसी संकट का इंतजार करता है।

03 जल मंत्री आतिशी के खोखले वादे को उजागर हुए -देवेंद्र यादव
06 ममता का बंगाल और बेखौफ अपराधी
08 सभी सरकारी कामकाज मातृभाषा उड़िया में होंगे ।

दिल्ली और भारत सरकार की कथनी और करनी में फर्क इलैक्ट्रिक वाहनों पर घोषित छूट की तत्काल प्रभाव से बंद

संजय बाटला

नई दिल्ली ।एक तरफ भारत सरकार और दिल्ली सरकार इलैक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की घोषणाएं करते नजर आती हैं और दूसरी तरफ अपने राजस्व में इजाफा करने के लिए इलैक्ट्रिक वाहनों पर दी गई टैक्स और पंजीकरण फीस को बिना पूर्व सूचना के जारी कर जनता को हतप्रभ कर रही है। कल तक इलैक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स और वाहन पंजीकरण फीस जीरो थी जो आज अन्य फ्यूल श्रेणी के वाहनों से ली जा रही थी वह इलैक्ट्रिक वाहनों को खरीदने वालों से ली गई। इस बाबत जानकारी प्राप्त करनी चाही तो परिवहन विभाग के किसी भी अधिकारी ने इस बाबत कोई भी जानकारी नही दी और साथ ही बताया उन्हें भी नही पता की कब और किसके कहने पर यह लागू हुई है। इलैक्ट्रिक वाहन शाखा के उपायुक्त कार्यालय में नही मिले और ना ही उन्होंने फोन उठाना उचित समझा। **दिल्ली परिवहन विभाग राजस्व इजाफा करवाने के लिए पिछले 5 वर्षों से सुर्खियों मे है ही पर साथ में भारत सरकार द्वारा भी इस बाबत जनता को कोई जानकारी प्रदान नहीं करना आश्चर्य की बात के साथ यह सिद्ध करता है की राजस्व इजाफा के लिए कोई भी अलग नही ना राज्य सरकार और ना ही भारत सरकार**। विश्वस्त सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार परिवहन विभाग दिल्ली में **इलैक्ट्रिक वाहन शाखा के उपायुक्त ओम ढोले द्वारा बीते कल एनआईसी को खबर भिजवा कर तत्काल प्रभाव से इलैक्ट्रिक वाहनों पर टेक्स और पंजीकरण फीस लागू कर आनलाइन आज से शुरु करने के दिशा निर्देश जारी किए थे और साथ ही पता चला की उनके कहे अनुसार तो टैक्स और पंजीकरण फीस 1 अप्रैल से ही लेने शुरु हो जाने चाहिए थे फिर क्यों नहीं लिए गए** अब उनको यह आदेश किसने दिए यह बताने के लिए वह उपलब्ध नहीं थे। **अब प्रश्न यह उठता है की किस आधार पर भारत सरकार और दिल्ली सरकार यह दावा करती है की इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए वह बहुत कुछ कर रहे हैं और बजट के अंतर्गत इसके लिए घोषणाएं कर रहे हैं**। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के बाद तत्काल दिल्ली के इलेक्शन आ रहे हैं ऐसे में जनता को इस प्रकार का झटका देना क्या सिद्ध करता है यह हम से बेहतर जनता स्वयं जानती है। **बढ़ते प्रदूषण से मुक्त होने के लिए इलैक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों का बढ़ावा अति आवश्यक है** पर क्या इस श्रेणी के वाहनों जो जनता के बजट से ऊपर है पर सब्सिडी बंद करना, टैक्स और पंजीकरण फीस लागू करना जनता को इस श्रेणी के वाहनों को खरीदने में सहायक बनेगा या पीछे हटाएगा, बड़ा सवाल ? **कही इसके पीछे परिवहन विभाग दिल्ली, आप पार्टी दिल्ली सरकार और भारत सरकार की मिलीभगत से कोई मंशा तो छुपी हुई नही। कही परिवहन विभाग दिल्ली, आप पार्टी दिल्ली सरकार और भारत सरकार प्रदूषण के नाम पर फिर से जनता को कोई बड़ा जुर्माना लगाने की सोच तो नही** रहे पिछले कई दिनों से आने वाली वर्षा ने यह तो सिद्ध करवा ही दिया की **दिल्ली में प्रदूषण वाहनों, फैक्ट्रियों और तंदूर के धुएं से नही बढ़ता है यह बढ़ता है दिल्ली सरकार की स्वयं की गलतियों के कारण। दिल्ली की सड़को और पेड़ पौधे से धूल मिट्टी की सफाई कराने में असमर्थ दिल्ली सरकार अपनी गलती के एवज में दिल्ली की जनता पर ही इल्जाम लगा कर अरबों रुपए चालान में वसूल कर राजस्व में ले रही है** आपको आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार और बीजेपी भारत सरकार की कथनी और करनी बताना हमारी जिम्मेदारी थी और साथ ही यह जानकारी पहुंचाना की अब आज से **इलैक्ट्रिक वाहन को खरीदने पर आपको मिलने वाली छुट उपलब्ध नहीं है क्योंकि दोनो सरकारों ने आने वाले इलेक्शन को देखते हुए अपना हाथ खींच लिया है।**

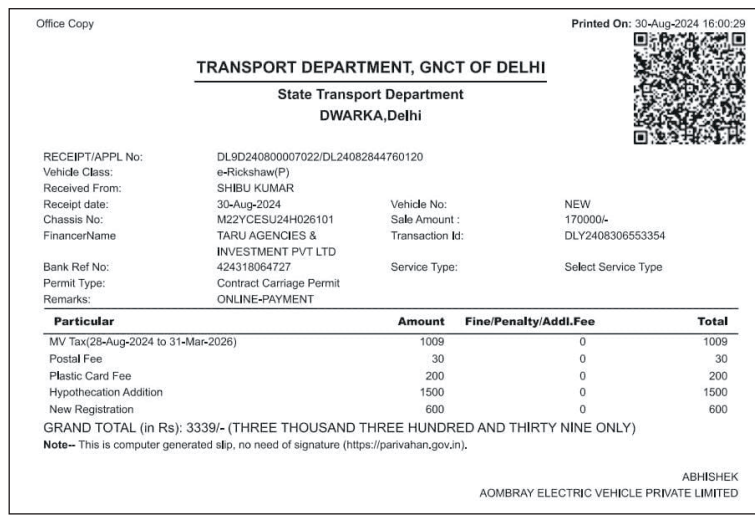

Office Copy

Printed On: 30-Aug-2024 16:00:29

TRANSPORT DEPARTMENT, GNCT OF DELHI

State Transport Department

DWARKA,Delhi

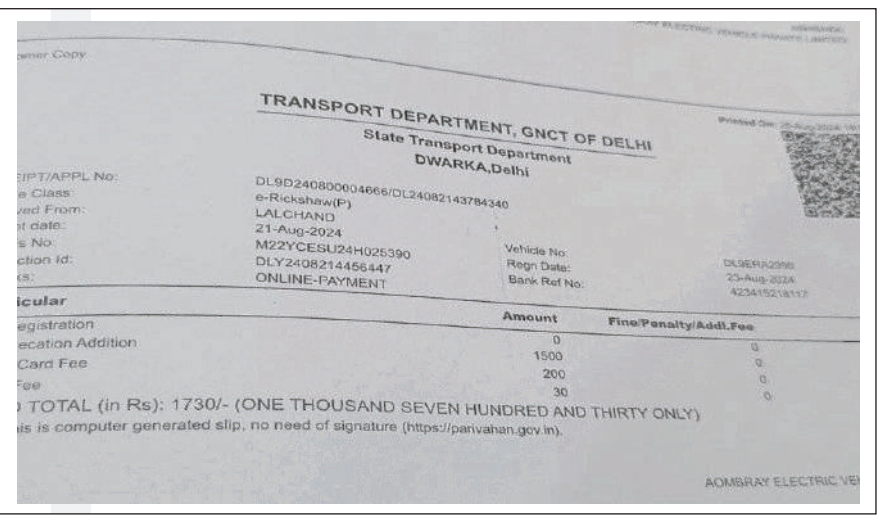

RECEIPT/APPL No:	DL9D240800007022/DL24082844760120		
Vehicle Class:	e-Rickshaw(P)		
Received From:	SHIBU KUMAR		
Receipt date:	30-Aug-2024	Vehicle No:	NEW
Chassis No:	M22YCESU24H026101	Sale Amount :	170000/-
FinancerName	TARU AGENCIES & INVESTMENT PVT LTD	Transaction Id:	DLY2408306553354
Bank Ref No:	424318064727	Service Type:	Select Service Type
Permit Type:	Contract Carriage Permit		
Remarks:	ONLINE-PAYMENT		

Particular	Amount	Fine/Penalty/Addl.Fee	Total
MV Tax(28-Aug-2024 to 31-Mar-2026)	1009	0	1009
Postal Fee	30	0	30
Plastic Card Fee	200	0	200
Hypothecation Addition	1500	0	1500
New Registration	600	0	600

GRAND TOTAL (in Rs): 3339/- (THREE THOUSAND THREE HUNDRED AND THIRTY NINE ONLY)

Note-- This is computer generated slip, no need of signature (https://parivahan.gov.in).

ABHISHEK
AOMBRAY ELECTRIC VEHICLE PRIVATE LIMITED

TRANSPORT DEPARTMENT, GNCT OF DELHI
State Transport Department
DWARKA,Delhi

TOTAL (in Rs): 1730/- (ONE THOUSAND SEVEN HUNDRED AND THIRTY ONLY)
is is computer generated slip, no need of signature (https://parivahan.gov.in).

सड़क परिवहन मंत्रालय ने स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम या वाहन स्क्रैपिंग नीति शुरू की

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली । सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में अयोग्य प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की प्रणाली बनाने के लिए स्वैच्छिक वाहन आधुनिकीकरण कार्यक्रम या वाहन स्क्रैपिंग नीति शुरू की है। कार्यक्रम और नीति को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं और स्वचालित परीक्षण स्टेशनों के नेटवर्क के माध्यम से लागू किया जाएगा।

इस संबंध में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत मंडपम में सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और अजय टम्टा की उपस्थिति में भारतीय वाहन निर्माताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तृत बातचीत की। चर्चा का उद्देश्य कबाड़ हो चुके निजी स्वामित्व वाले वाणिज्यिक और यात्री वाहनों को हटाने उनकी जगह कम प्रदूषण वाले नए वाहनों को लाने की रणनीति तैयार करना था।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि चर्चा के बाद, कई वाणिज्यिक और यात्री वाहन निर्माता स्क्रैपेज सर्टिफिकेट के खिलाफ सीमित अवधि के लिए छूट देने पर सहमति बनी हैं। इसमें कहा गया है, वाणिज्यिक वाहन और यात्री वाहन निर्माताओं ने क्रमशः दो साल और एक साल की सीमित अवधि के लिए छूट देने की इच्छा दिखाई है।

विश्व बैंक प्रतिनिधिमंडल ने एनसीआरटीसी का दौरा किया, शहरी पारगमन में सहयोग पर चर्चा की

विश्व बैंक के एक प्रतिनिधिमंडल ने एनसीआरटीसी कार्यालय का दौरा किया। उन्होंने आगामी आरआरटीएस गलियारों के वित्तपोषण पर ध्यान देने के साथ शहरी पारगमन में चल रहे और भविष्य के सहयोग पर चर्चा की।

परिवहन विशेष न्यूज

विश्व बैंक के एक प्रतिनिधिमंडल ने एनसीआरटीसी कार्यालय का दौरा किया और आगामी आरआरटीएस गलियारों के वित्तपोषण पर ध्यान देने के साथ शहरी पारगमन में चल रहे और भविष्य के सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, जिसे रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) दिल्ली-गुरुग्राम-एसएनबी कॉरिडोर को वित्त पोषित करने के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।

उन्होंने पहले विभिन्न पहलों पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) के साथ साझेदारी की थी, जिसमें आरआरटीएस गलियारों के माध्यम से रसद सेवाएं प्रदान करने और आगामी मार्गों पर पारगमन-उन्मुख विकास संभावनाओं की खोज पर अध्ययन शामिल था। यह सहयोग न केवल वित्तीय सहायता सुनिश्चित करेगा बल्कि अतिरिक्त पूंजी और साझेदार जुटाने के लिए विश्व बैंक की वैश्विक विशेषज्ञता का भी लाभ उठाएगा। अधिकारियों ने कहा कि बैंक ने आरआरटीएस परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए एडीबी के साथ चार अग्रिम संयुक्त मिशन आयोजित किए हैं।

उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल ने एनसीआरटीसी के साथ स्थानीय और वैश्विक स्तर पर और सहयोग तलाशने में रुचि व्यक्त की, जो साझेदारी को मजबूत करने और भविष्य के शहरी पारगमन विकास का मार्ग प्रशस्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आरआरटीएस का कार्यान्वयन क्षेत्र में भीड़भाड़ और प्रदूषण को संबोधित करने के लिए एक व्यापक रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए व्यापक कार्य योजना का हिस्सा है और दिल्ली में यातायात को कम करने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों का पालन करता है।

आठ चिन्हित गलियारों में से तीन को पहले चरण में प्राथमिकता दी गई है। दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ, दिल्ली-गुरुग्राम-एसएनबी और दिल्ली-पानीपत। वर्तमान में, दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के 42 किलोमीटर के हिस्से पर सेवाएं चालू हैं। पूरा 82 किलोमीटर का कॉरिडोर जून 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है।

सड़क सुरक्षा संवाद: एक भारतीय का भारतीय के लिए

- डॉ. अंकुर शरण

जब हम घर से निकलते हैं, तो हमारी दिन की शुरुआत सड़क से ही होती है। चाहे कहीं जाने के लिए हो या किसी से मिलने के लिए, हम सभी सड़क का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सोचिए, कितने ऐसे लोग हैं जो निकलते तो हैं, मगर कभी सही-सलामत घर वापस नहीं लौट पाते, या फिर अपने परिवार से मिल नहीं पाते। यह दुखद हकीकत है कि सड़क सुरक्षा से जुड़े हादसे आए दिन अखबारों की सुर्खियां बनते हैं।

आजकल सड़कों पर घूमते आवारा मवेशियों के कारण हो रही दुर्घटनाएं चिंता का विषय हैं। सड़क पर बैठे पशुओं के कारण अक्सर हादसे होते हैं, जिससे लोग घायल होते हैं और कभी-कभी तो उनकी जान भी चली जाती है। इन घटनाओं से कैसे बचाव किया जा सकता है, इस पर विचार करना आवश्यक है।

ऐसी ही एक घटना हाल ही में मेरे साथ भी हुई जब मैं फरीदाबाद से गुरुग्राम का सफर कर रहा था। आमतौर पर एक घंटे का यह सफर इस बार ढाई घंटे में पूरा हुआ, क्योंकि रास्ते में जगह-जगह गड्ढे थे और बीच सड़क पर बैठे पशुओं की वजह से जाम लग गया था। यह समस्या सिर्फ मेरी नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो इन सड़कों पर यात्रा करता है।

आवारा मवेशियों से सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के कुछ प्रमुख उपाय:

स्थानीय प्रशासन की भूमिका: प्रशासन को सड़कों पर घूमते आवारा मवेशियों को पकड़ने और उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखने की योजना बनानी चाहिए। इसके लिए विशेष अभियान चलाए जा सकते हैं।

जानकारी साझा करें: यदि आप सड़कों पर आवारा मवेशी देखते हैं, तो उनकी तस्वीरें खींचकर संबंधित अधिकारियों को भेजें। इसके अलावा, सोशल मीडिया पर #VocalForLocalRoadSafety टैग करके इस समस्या को उजागर करें, ताकि यह मुद्दा व्यापक स्तर पर देखा जा सके।

स्थानीय जागरूकता: स्थानीय समुदायों को भी इस समस्या के प्रति जागरूक होना चाहिए और अपने पशुओं को खुला न छोड़ें। यदि हर नागरिक इस बात का ध्यान रखेगा, तो इस समस्या से काफी हद तक निपटा जा सकता है।

सड़क की देखभाल: सड़कों पर गड्ढों को तुरंत भरने के लिए संबंधित विभागों को सक्रिय रहना चाहिए। यदि सड़कों की स्थिति अच्छी होगी, तो दुर्घटनाओं का खतरा भी कम होगा।

जनभागीदारी: छोटी-छोटी चीजें जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में कर सकते हैं, उनसे सड़क सुरक्षा के प्रति न केवल हम स्वयं सतर्क रह सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी सतर्क कर सकते हैं।

हमारे भारतवर्ष को गर्वित करने के लिए किसी बड़ी चीज की जरूरत नहीं है, बस छोटी-छोटी सावधानियां बरतकर हम बड़ी दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक होकर हम अपने समाज को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान कर सकते हैं।

चलें, हम सब मिलकर इस दिशा में प्रयास करें और एक सुरक्षित भारत का निर्माण करें।

इस दिन रखा जाएगा हरतालिका तीज का व्रत, सोलह पत्तियों का क्या है महत्व?

हिन्दू पंचांग के अनुसार, हरतालिका तीज का व्रत भादो महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर रखा जाता है। इस साल भादो महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 5 सितंबर को दोपहर 12 बजकर 21 मिनट से शुरू होगी और 6 सितंबर को दोपहर 3 बजकर 1 मिनट पर खत्म होगी। ऐसे में व्रत 6 सितंबर को रखा जाएगा।

हिंदू धर्म में कई तीज मनाई जाती हैं, जिनमें से एक हरतालिका तीज भी है। हरतालिका तीज सुहागन स्त्रियों के लिए काफी मायने रखती है। इस दिन व्रत रखने से सुहागन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है और शादीशुदा जीवन में खुशहाली आती है। कुंवारी लड़कियां भी अच्छा वर पाने के लिए ये व्रत रखती हैं। इस व्रत को निराहार और निर्जला किया जाता है। पंडितों का मनाना है कि इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए किया था।

5 या 6 कब रखा जाएगा हरतालिका तीज का व्रत?

हिन्दू पंचांग के अनुसार, हरतालिका तीज का व्रत भादो महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर रखा जाता है। इस साल भादो महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 5 सितंबर को दोपहर 12 बजकर 21 मिनट से शुरू होगी और 6 सितंबर को दोपहर 3 बजकर 1 मिनट पर खत्म होगी। ऐसे में हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर को रखा जाएगा। इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा-अर्चना की जाएगी।

हरतालिका तीज व्रत में ऐसे करें पूजा

हरतालिका तीज की पूजा सुबह न कर सूर्यास्त के बाद प्रदोषकाल में की जाती है। साथ ही शिव शंकर, पार्वती और गणेश जी की हाथों से बालू रेत और काली मिट्टी की प्रतिमा बनायी जाती है। पूजा की जगह को फूलों से सजाकर एक चौकी रखकर उस पर केले के पत्ते बिछाएं और शंकर, पार्वती तथा भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा करें। इस पूजा में पार्वती जी को सुहाग की सभी वस्तुएं अर्पित की जाती है। तीज की कथा सुनें और रात्रि जागरण करें फिर आरती के बाद सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं और हलवे का भोग लगाकर व्रत खोलें।

हरतालिका तीज व्रत व्रत से जुड़े नियम

हरतालिका तीज व्रत अखंड सुहाग का प्रतीक होता है। इस व्रत को निर्जला रहा जाता है और व्रत के दूसरे दिन जल ग्रहण किया जाता है। व्रत के सुबह पूजा के बाद जल पीकर व्रत खोला जाता है। इस व्रत की खास बात यह है कि एक बार इस व्रत को प्रारम्भ करने के बाद छोड़ा नहीं जाता है। साथ ही दिन में व्रत रखकर रात में जागरण कर भजन-कीर्तन करना चाहिए।

हरतालिका तीज व्रत पर सोलह पत्तियों का क्या है महत्व

हरतालिका तीज व्रत के प्रभाव से महिलाओं को पति की दीर्घायु, परिवार के सुख-शांति और सुयोग्य वर प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन पूजा में 16 प्रकार की इच्छपूर्ती पत्तियां महादेव-मां पार्वती को जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे गौरीशंकर जल्दी प्रसन्न होते हैं।हरतालिका तीज की पूजा में बेलपत्र, तुलसी, जातीपत्र, सेवंतिका, बांस, देवदार पत्र, चंपा, कनेर, अगस्त्य, भृंगराज, धतूरा, आम पत्ते, अशोक पत्ते, पान पत्ते, केले के पत्ते, शमी के पत्ते भोलेनाथ और पार्वती को विशेषतौर पर चढ़ाना चाहिए।

मेरठ से एकदम नजदीक है ये हिल स्टेशन, महज 2 घंटे का सफर करने के बाद जन्नत का मजा लें

सितंबर से लेकर नवंबर महीने तक पहाड़ों पर घूमने का अलग ही मजा होता है। यहां पर सुंदर घाटियां, खूबसूरत वन और पहाड़ी वादियों से आपको प्यार हो जाएगा। अगर आप पहाड़ों पर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यह समय सबसे बढ़िया है। मेरठ से एकदम नजदीक है यह हिल स्टेशन। यहां पर पहाड़ों के सुदर नजारे देख सकते हैं। आइए जानते हैं मेरठ से एकदम पास सबसे बेस्ट हिल स्टेशन कौन-से हैं।

रानीखेत

अगर आप रानीखेत को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप यहां जा सकते हैं। मेरठ से रानीखेत की दूरी लगभग 320 किलोमीटर है। इसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। रानीखेत आप महज 5-6 घंटे की ड्राइव करके आराम से पहुंच सकते हैं। यहां सुंदर नजारे देखने को आपको मिलेंगे।

औली

मेरठ लगभग 400 किलोमीटर दूर औली एक शानदार हिल स्टेशन है। यहां आप अपनी जिंदगी के सुकून के पल बिता सकते हैं। देवदार और चीड़ के वृक्ष, सेब के बाग इस हिल स्टेशन की सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। यह हिल स्टेशन टूरिस्टों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है।

हर्षिल घाटी

मेरठ से महज 400 किलोमीटर दूर है हर्षिल वैली एक सुंदर हिल स्टेशन है। यहां आप ड्राइव करके आसानी से पहुंच सकते हैं। यहां पर सुंदर घाटियां, खूबसूरत वन और पहाड़ी वादियों से आपको प्यार हो जाएगा।

अल्मोड़ा

कुमाऊं पर्वत श्रृंखला पर मौजूद अल्मोड़ा एक सुंदर हिल स्टेशन है। यहां आप मेरठ से लगभग 6 घंटे का सफर करके पहुंच सकते हैं। यहां आप मां नंदा देवी मंदिर, नौकुचिया ताल और कई सारी खूबसूरत जगहें एक्सप्लोर कर सकते हैं।

चकराता

मेरठ से करीब 280 किलोमीटर दूर है चकराता। यह एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। यहां पर आप हिमालय की शानदार रेंज देख सकते हैं। खूबसूरत घाटियां देखकर आपको काफी सुकून मिलेगा।

कानाताल

मेरठ से लगभग 240 किलोमीटर दूर है कानाताल। यह हिल स्टेशन काफी छोटा है लेकिन घूमने के लिए एकदम बढ़िया है। यहां आप कभी भी जा सकते हैं।

ऋषिकेश

मेरठ से सबसे नजदीक ऋषिकेश पड़ता है। यहां आप 2 घंटे का सफर करके आसानी से पहुंच सकते है। यहां आप रिवर राफ्टिंग, त्रिवेणी घाट और मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं।

हर स्किन टाइप के लिए बेस्ट हैं ये ग्रीन टी के फेस पैक, मिलेगी ग्लोइंग स्किन

ग्रीन टी में कई शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। ग्रीन टी का फेसपैक लगाने से पिंपल्स से छुटकारा मिलता है और यह पोर्स को क्लीन करता है। इससे बार-बार फेस पर मुंहासे नहीं आते हैं और चेहरे पर मौजूद दाग-धब्बे भी कम होते हैं।

ग्रीन टी में कई शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। जो वेट लॉस में काफी मददगार मानी जाती हैं। वहीं सुबह चाय की जगह रोजाना ग्रीन टी पीना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसको पीने से शरीर को कई फायदे मिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्रीन टी पीने के साथ ही स्किन को ग्लोइंग बनाने के काम भी आती है। आप ग्रीन टी का फेसपैक बनाकर चेहरे पर अप्लाई करें। बता दें कि ग्रीन टी का फेस पैक हर स्किन टाइप के लिए लाभकारी होता है।

इसके फेस पैक से पिंपल्स से छुटकारा मिलता है और यह पोर्स को क्लीन करता है। इससे बार-बार फेस पर मुंहासे नहीं आते हैं और चेहरे पर मौजूद दाग-धब्बे भी कम होते हैं। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको अलग-अलग तरीके के ग्रीन टी के फेस पैक के बारे में बताने जा रहे हैं।

ड्राई स्किन के लिए ग्रीन टी फेस पैक

ड्राई स्किन के लिए ग्रीन टी का फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले ग्रीन टी को उबाल लें और इस मिक्सर में पीस लें। अब इसमें एक चम्मच शहद और दही मिलाकर फेस पर अप्लाई करें। यह फेस पैक स्किन को नमी देने के साथ ग्लो भी बढ़ाता है। ग्रीन टी के पानी के साथ भी यह फेस पैक बनाकर तैयार कर सकती हैं। इस फेस पैक का टेक्स्चर सही रखने के लिए आधा छोटा चम्मच बेसन मिला लें।

ऑयली स्किन के लिए ग्रीन टी फेस पैक

ऑयली स्किन वाले लोग एक बड़ा चम्मच ग्रीन टी को थोड़े पानी में उबाल लें। इस इस पानी में मुल्तानी मिट्टी और कुछ बूंद नींबू का रस मिलाकर पेस्ट बना लें। फिर अपना चेहरा धो कर सुखा लें। अब इस फेसपैक को 15-20 मिनट के लिए अप्लाई करें और चेहरा नॉर्मल पानी से धो लें। यह फेस पैक एक्स्ट्रा ऑयल को फेस पर आने से रोकता है और यह पिंपल्स से भी छुटकारा दिलाने का काम करता है।

कॉम्बिनेशन स्किन के लिए ग्रीन टी फेस पैक

बता दें कि कुछ लोगों की माथे, नाक और ठुड्डी की आसपास की त्वचा ऑयली होती है। तो अन्य हिस्से थोड़े रुखे होते हैं। ऐसी त्वचा के लिए ओटमील में ग्रीन टी का पानी मिलाएं और एक चम्मच शहद मिलाकर कुछ देर के लिए छोड़ दें। अब जब ओटमील मुलायम हो जाए, तो इसको फेस पर अप्लाई करें और फिर 15 मिनट बाद चेहरा धो लें।

शरीर को सूखा कर देगी विटामिन बी12 की कमी, रात में दिखें ये लक्षण तो नजरअंदाज न करें

अगर शरीर में विटामिन बी12 की कमी होती है तो शरीर एकदम से सूख जाता है। विटामिन बी12 की कमी से रात में इसके कई लक्षण नजर आते हैं। इस विटामिन के कई गंभीर लक्षण रात के समय पर नजर आते हैं, यहां हम आपको कुछ संकेत बताने जा रहे हैं, जो रात के समय नजर आते हैं।

शरीर में पर्याप्त न्यूट्रिशन होना काफी जरुरी है। अगर आप अपनी डाइट में विटामिन बी12 के फूड्स का सेवन नहीं करते तो आपका शरीर जल्द ही मुसीबत में आ सकते हैं। शरीर में विटामिन बी12 की कमी से स्ट्रोक, हार्ट अटैक, नर्वस सिस्टम में खराबी जैसी समस्याएं होने लगती है, जो व्यक्ति को रोगी बना देता है। विटामिन बी12 की कमी के लक्षण को तुरंत पहचाने और इसके उपाय करना भी जरुरी है। इस विटामिन के कई गंभीर लक्षण रात के समय पर नजर आते हैं, यहां हम आपको कुछ संकेत बताने जा रहे हैं, जो रात के समय नजर आते हैं।

रात को दिखने वाले बी12 की कमी के लक्षण

- नींद भर की थकान के बाद बेड पर जाने पर आमतौर पर शरीर की मांसपेशियों में दर्द का अनुभव होता है। अगर आपके मसल्स में रोजाना ऐंठन और कमजोरी का अनुभव कर रहे हैं, तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। यह बी12 की कमी हो सकती है।

- अगर रात के समय में यदि आपको ज्यादा पेट या डाइजेशन से जुड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो इसे नजरअंदाज ना करें। मतली, दस्त, गैस, कब्ज जैसी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के लक्षण वास्तव में बी12 की कमी का नतीजा हो सकता है।

- रात के समय सिर में दर्द की समस्या आम हो सकती है। अगर रात के समय रोज सिरदर्द हो रहा है तो यह विटामिन बी12 की कमी हो सकती है।

- अगर आपको भी रात को नींद नहीं आती है तो आप बॉडी में बी12 की कमी हो सकती है। यदि आप काफी समय से सो नहीं पा रहे हैं तो डॉक्टर को जरुर एक बार दिखाएं।

- जब आप सोते हैं तो उस समय लेटे-लेटे ही पैरों की नसें अपने आप तन जाती है, तो इसे नजरअंदाज करना आपके लिए मुसिबत लेकर आ सकता है। यह बी12 की कमी का एक साइलेंट लक्षण है।

बारिश के मौसम में बना रहे घूमने का प्लान तो इन बातों का रखें खास ख्याल, दोगुना होगा ट्रिप का मजा

अगर आप भी इस मौसम में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। जिससे कि आपको ट्रिप के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

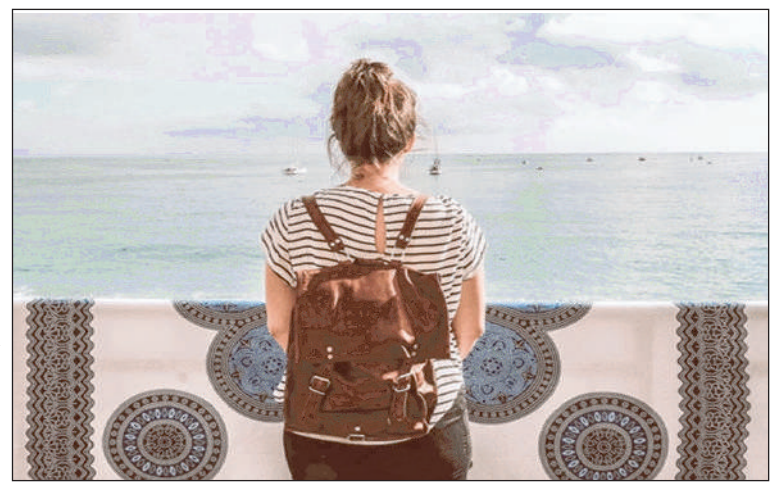

भीषण गर्मी के बाद लोग मानसून का बेसब्री से इंतजार करते हैं। बारिश के मौसम में लोग घरों में चाय और पकोड़े का लुत्फ उठाते हैं। तो वहीं कुछ लोगों को मानसून में घूमना-फिरना काफी ज्यादा पसंद होता है। लेकिन बारिश के मौसम में घूमना काफी रिस्की भी हो सकता है। ऐसे में अगर आप भी इस मौसम में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। जिससे कि आपको ट्रिप के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि मानसून में घूमने जाने के दौरान किन बातों का ख्याल रखना चाहिए।

मौसम की जानकारी है जरूरी

अगर आप भी बारिश के मौसम में घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो मौसम की पूरी जानकारी पहले से रखें। इससे आपको पता रहेगा कि कैसा मौसम रहने वाला है। बता दें कि यह आपके और आपके परिवार या दोस्तों की सुरक्षा के लिहाज से काफी जरूरी है।

वॉटर प्रूफ बैग

मानसून में सामान को सेफ रखने के लिए वॉटर प्रूफ बैग कैरी करें। क्योंकि यदि आप बारिश में भीग भी जाते हैं, तो आपका सामान सुरक्षित रहेगा और कुछ प्लास्टिक के छोटे जिपलॉक बैग्स रखें। जिसमें अपना फोन और वॉलेट रख सकते हैं।

सही कपड़े और जूते चुनें

बारिश के मौसम में नमी के कारण काफी उमस होने लगती है। जिसके कारण पसीना बहुत आता है। इसलिए ट्रिप के दौरान ऐसे कपड़े पैक करें, जिनको पहनने से आपको कम गर्मी लगे। वहीं ऐसे जूते रखें, जिनको आप आसानी से सुखा सकते हैं। बारिश में ग्रिप वाले जूते पहनें।

बीमारियों से बचाव

मानसून में मच्छरों का भी काफी ज्यादा आतंक बढ़ जाता है। ऐसे में मच्छरों से अपना बचाव करने के लिए मॉइस्क्यूटो रिपेलेंट रखें और फुल बाजू वाले कपड़े पहनें। वहीं बाहर खाना खाने के दौरान हाइजीन का खास ख्याल रखें।

जॅनिफ़र लोपैज़ और बेन एफ्लेक आखिरकार अलग हो गये, क्या अपने Ex के साथ रिश्ते में वापस आना एक बेहद बुरा विचार है! ये हैं वजह

जेनिफर लोपेज और बेन एफ्लेक का रोलरकोस्टर रोमांस आखिरकार 20 अगस्त को लोपेज द्वारा तलाक के लिए अर्जी दाखिल करने के साथ समाप्त हो गया है। 2002 में एक कदम पीछे हटने और एक साल के भीतर शादी की योजना बनाने के बाद, इस जोड़े की सगाई कुछ ही महीनों बाद समाप्त हो गई।

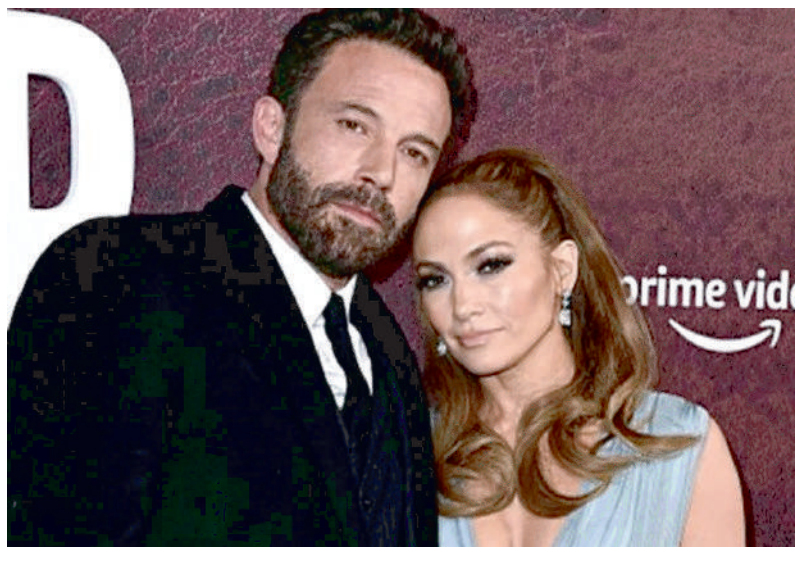

जेनिफर लोपेज और बेन एफ्लेक का रोलरकोस्टर रोमांस आखिरकार 20 अगस्त को लोपेज द्वारा तलाक के लिए अर्जी दाखिल करने के साथ समाप्त हो गया है। 2002 में एक कदम पीछे हटने और एक साल के भीतर शादी की योजना बनाने के बाद, इस जोड़े की सगाई कुछ ही महीनों बाद समाप्त हो गई। 2021 में जब एफ्लेक को लोपेज के लास वेगास स्थित घर में देखा गया, तो उनके रिश्ते ने फिर से सुर्खियाँ बटोरीं, जिसके बाद 2022 में उनकी दूसरी सगाई हुई और फिर शादी हुई। मई 2024 में तेजी से आगे बढ़ते हुए, अलगाव की अफवाहें फिर से सामने आने लगीं क्योंकि उन्हें शायद ही कभी एक साथ देखा गया हो। अब, लोपेज ने तलाक के लिए अर्जी दाखिल की है, जो उनके बीच के रिश्ते में एक और मोड़ ला रहा है।

उनकी कहानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल को सुर्खियों में लाती है: क्या अपने पूर्व साथी के साथ फिर से जुड़ना कभी भी एक अच्छा विचार है? किसी पुराने रिश्ते को फिर से जगाना एक गर्मजोशी और परिचित सुकून की तरह लग सकता है, लेकिन इससे अक्सर वही पुरानी समस्याएं फिर से उभर आती हैं। इसलिए, किसी पुराने रिश्ते में वापस जाने से पहले, यह विचार कर लेना चाहिए कि क्या यह जोखिम उठाने लायक है।

यहाँ 6 कारण दिए गए हैं कि आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए अपने पूर्व साथी के साथ फिर से जुड़ने से क्यों बचना चाहिए:

आप कम से समझौता कर सकते हैं:

चाहे किसी ने भी रिश्ता खत्म किया हो, लेकिन यह सच है कि ब्रेकअप किसी कारण से हुआ था। चाहे असंतोष के कारण हो या यह महसूस करने के कारण कि आप बेहतर के हकदार हैं, उसी रिश्ते में वापस लौटने का मतलब कम से समझौता करना हो सकता है। पुराने पैटर्न को दोहराने के बजाय, आप वास्तविक खुशी और मानसिक शांति के अवसर के हकदार हैं। इसका मतलब अक्सर वह सच्चा आनंद और विकास खोना होता है जो आपको किसी ऐसे व्यक्ति में मिल सकता है जो वास्तव में आपकी पसंद से मेल खाता हो।

अनसुलझे मुद्दे फिर से उभरेंगे:

ब्रेकअप किसी कारण से होता है। यदि अंतर्निहित मुद्दों का समाधान नहीं किया जाता है, तो उनके फिर से उभरने की संभावना है। किसी पूर्व साथी के पास वापस लौटना, खासकर यदि वे इन समस्याओं को संबोधित नहीं कर रहे हैं, तो वही पुरानी परेशानियाँ पैदा कर सकता है। खुद को इस नाटक से दूर रखना समझदारी है।

अंतहीन चक्र से बचें:

जोड़ों को बार-बार टूटते और फिर से मिलते देखना परिचित लग सकता है। अगर आप पहले भी इस चक्र में फंस चुके हैं, तो इससे बाहर निकलने के लिए अपने पिछले अनुभवों पर भरोसा करें। अपने पूर्व साथी के साथ वापस आना अक्सर चक्र को फिर से शुरू कर देता है। इससे आपको सिर्फ़ अपनी मानसिक शांति खोनी पड़ेगी।

भावनात्मक रूप से अपमानजनक हो सकता है:

अपने पूर्व साथी के साथ फिर से जुड़ने से पुराने पैटर्न फिर से उभर सकते हैं, जिसमें हल्के में लिया जाना और भावनात्मक संकट को सहन करना शामिल है। इस तरह का हेरफेर स्पष्ट रूप से भावनात्मक दुर्व्यवहार का एक रूप है जो अनावश्यक है। इसलिए, इससे दूर रहना और अपनी भावनात्मक भलाई की रक्षा करना बेहतर है।

यह भावनात्मक रूप से थका देने वाला हो सकता है:

अपने पूर्व साथी के साथ वापस आने के बारे में सोचते समय आराम की भावना आती है, लेकिन जो आरामदायक लगता है वह आपकी भावनात्मक ऊर्जा को खत्म कर सकता है। आप खुद को इतना प्रयास करते हुए पा सकते हैं कि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा करते हैं। खुद को अनावश्यक भावनात्मक तनाव से बचाएं।

लोग रातों-रात नहीं बदलते:

मौलिक गुण जल्दी नहीं बदलते, इसलिए अपने पूर्व साथी में अस्थायी बदलावों से खुश न हों। अगर ये सुधार इतने महत्वपूर्ण थे, तो वे पहले क्यों नहीं दिखे? इस सवाल पर विचार-मंथन करने से आपको अस्थायी सुधारों को समझने और गलती दोहराने से बचने में मदद मिल सकती है।

दिल्ली में इस महीने हुई बीते 13 साल के मुकाबले अधिक बारिश, तापमान ने तोड़ा चार साल का रिकॉर्ड

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली में लगातार तीसरे दिन बारिश का दौर जारी है। इस बारिश ने 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहीं अधिकतम तापमान भी सामान्य से छह डिग्री नीचे रहते हुए बीते चार साल का रिकॉर्ड टूट गया है। बारिश के कारण दिल्लीवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में जलभराव के कारण जाम लग गया है।

नई दिल्ली। लगातार तीसरे दिन राजधानी में बृहस्पतिवार को हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा का दौर जारी रहा। इससे दिल्लीवासियों को उमस भरी गर्मी से भी खासी राहत मिली है। आलम यह है कि अगस्त में वर्षा ने जहां 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

वहीं बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान ने भी सामान्य से छह डिग्री नीचे रहते हुए बीते चार साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हालांकि मौसम विभाग की मानें शुक्रवार को हल्की वर्षा ही होने का अनुमान है। वहीं वर्षा के कारण राजधानी वासियों को खासी परेशानी का सामना भी करना पड़ा।

सुबह से ही वर्षा का दौर जारी

बृहस्पतिवार को भी सुबह से ही वर्षा का दौर जारी रहा। दिन में भी बादल छाए रहे और रुक रुककर कहीं हल्की तो कहीं तेज वर्षा दर्ज की गई। अधिकतम तापमान सामान्य से छह डिग्री कम 28.8 डिग्री रहा। यह अगस्त माह का 2020 के बाद सबसे कम अधिकतम तापमान है। बुधवार को यह 34.0 डिग्री रहा था।

न्यूनतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री कम 23.0 डिग्री रिकॉर्ड किया। हवा में नमी का स्तर 100 से 95 प्रतिशत दर्ज हुआ। जहां तक वर्षा का सवाल है तो सुबह साढ़े आठ बजे तक 77.1 मिमी जबकि सुबह साढ़े आठ बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक 11.8 मिमी वर्षा हुई।

13 साल में इस माह सर्वाधिक बारिश

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इस साल अगस्त में अभी तक दिल्ली में 378.5 मिमी वर्षा हो चुकी है। यह पिछले 13 साल में इस माह की सर्वाधिक है। इससे पूर्व 2010 में 455.1 मिमी बरसात दर्ज की गई थी।

मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि शुक्रवार को भी सामान्यतया बादल छाए रहेंगे। गर्जन वाले बादल बनने और हल्की बरसात होने की संभावना है। अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमशः 34 व 24 डिग्री रह सकता है।

दिल्ली की हवा लगातार साफ चल रही

उधर, हवाओं और वर्षा के असर से दिल्ली की हवा लगातार साफ चल रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक बुधवार को दिल्ली का एक्यूआई 60 दर्ज किया गया। इस स्तर की हवा को "संतोषजनक" श्रेणी में रखा जाता है। हाल फिलहाल इसमें बदलाव के आसार नहीं हैं।

चलते जाम में वाहन रेंगते हुए नजर आए

अब अगर परेशानी की बात करें तो बृहस्पतिवार को भी जलभराव के चलते जाम में वाहन रेंगते हुए नजर आए। सबसे ज्यादा परेशानी की बात यह थी कि वर्षा दफ्तर और स्कूल जाने के समय पर हुई। ऐसे में लोग समय पर अपने गंतव्य नहीं पहुंच सके। वर्षा का सर्वाधिक असर, पूर्वी, दक्षिणी और बाहरी दिल्ली के इलाकों में हुआ। जहां मुख्य मार्गों से लेकर रिहायशी इलाकों में जलभराव की समस्या उत्पन्न हुई।

कई इलाकों में जलभराव के कारण जाम लगा रहा

वर्षा सुबह होने की वजह से लोगों को जरूरी वस्तुएं जैसे दूध, ब्रेड, अखबार लाने में भी परेशानी हुई। पूर्वी दिल्ली के लोनी रोड, भजनपुरा, सादतपुर, श्रीराम कॉलोनी, करावल नगर, पटपड़गंज रोड़, मंडावली, वेस्ट विनोद नगर के पास एनएच-नौ की सर्विस रोड पर दुघनों से अधिक पानी हो गया। इसी तरह दक्षिणी दिल्ली रिंग रोड स्थित धौला कुआं, वसंत विहार, मालवीय नगर आदि क्षेत्रों में जलभराव के कारण जाम लगा रहा।

नौकरी पेशा लोगों को एक घंटे तक का हुआ विलंब

नौकरी पेशा लोगों को गंतव्य तक पहुंचने में आधे से लेकर एक घंटे तक का विलंब हुआ। दोपहर तक इन मार्गों पर जाम लगा रहा। खानपुर टी प्वाइंट से लेकर तुगलकाबाद फोर्ट तक ड्रेनेज लाइन चौक (जाम) होने से आने- जाने वाले मार्ग पर पानी भरा रहा। वहीं संगम विहार जाने वाले रतिया मार्ग, तिगड़ी रोड पर भी जलजमाव रहा। इन मार्गों पर दोपहर तक यातायात प्रभावित रहा।

वहीं रेलवे ब्रिज, पुल प्रहलादपुर पर जलभराव के कारण बदरपुर से संगम विहार की ओर जाने वाले एमबी रोड पर भी जाम रहा। जाम को लेकर ट्रैफिक विभाग ने एडवाइजरी जारी की और लोगों को जाम वाले रास्तों की बजाय वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी। बदरपुर से मीठापुर की ओर जाने वाले मार्ग पर बने मीठापुर पुल पर वर्षा के कारण बड़ा गड्ढा बन गया।

महरौली रोड पर वर्षा के कारण पेड़ गिर गया

वहीं तुगलकाबाद फोर्ट के पास बदरपुर-महरौली रोड पर वर्षा के कारण पेड़ गिर गया। इसके चलते डा. करणी सिंह शूटिंग रेंज के पास एमबी रोड पर जाम लगा रहा। बाहरी दिल्ली में भी जीटी करनाल रोड, मुकरबा चौक, रोहतक रोड, टिकरी बार्डर से लेकर रोहिणी सेक्टर-21 के पास सोलंकी कॉम्प्लेक्स के पास रमेश एन्क्लेव का नाला ओवरफ्लो होने से कई फीट पानी भर गया। पानी इससे आगे सीएनजी पंप रोड पर करीब 500 मीटर तक जमा हो गया।

बेगम विहार, जैन नगर, कश्मीरी कालोनी समेत आसपास की कई कॉलोनियों में पानी भरने से बच्चों का पैदल स्कूल तक पहुंचना मुश्किल हो गया। काफी मशक्कत के बाद बच्चे स्कूल तक पहुंच सकें। काफी संख्या में बच्चे जलभराव के कारण स्कूल जाने में असमर्थ रहे। इन कालोनियों में जलभराव का मुख्य कारण पानी की निकासी को लेकर सही व्यवस्था नहीं है। हलांकि इन कालोनियों में सीवर लाइन तो बिछाई गई है, लेकिन इसे चालू नहीं किया जा सका है।

निगम को 16 स्थानों पर मिली जलभराव की सूचना

वर्षा और जलभराव के कारण निगम को 16 स्थानों पर जलभराव की शिकायत मिली जबकि 17 स्थानों पर पेड़ व उसके हिस्से गिरने की सूचना मिली। एमसीडी को ईस्ट पटेल नगर, आरके पुरम, तिहाड़ गांव, मंगलापुरी, जंगपुरा, लक्ष्मी नगर समेत अन्य इलाकों में जलभराव हुआ तो वहीं, विवेक विहार, शंकप रोड, साकेत, ईस्ट मोती बाग और सुल्तानपुरी समेत विभिन्न इलाकों में पेड़ या उसके हिस्से गिरे। एमसीडी के अनुसार शिकायतों पर समस्याओं के समाधान के लिए कर्मचारियों को लगाया गया इस पर कार्य किया गया।

बीजेपी में क्यों मंडराया गुटबाजी का खतरा? चुनाव से पहले दिल्ली में चल में रही उठापटक; दो मोर्चों के अध्यक्ष बदले

सुषमा रानी

दिल्ली भाजपा में बदलाव का दौर जारी है। छह जिलों के प्रभारियों को बदलने के बाद अब पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष और प्रभारी को हटा दिया गया है। इससे पार्टी में गुटबाजी बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे इन बदलावों से कार्यकर्ता नाराज हैं। पढ़िए आखिर भाजपा में गुटबाजी का खतरा क्यों मंडरा रहा है?

नई दिल्ली। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी दिल्ली भाजपा में इन दिनों बदलाव का दौर चल रहा है। छह जिलों के प्रभारियों को बदलने के बाद अब पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष के साथ ही प्रभारी को हटा दिया गया। इससे पदमुक्त किए गए नेताओं व उनके समर्थकों में नाराजगी है। चुनाव से पहले पार्टी में हो रहे बदलाव से गुटबाजी बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पिछले वर्ष एक अगस्त को अपनी टीम घोषित की थी। प्रदेश पदाधिकारियों के साथ ही मोर्चों के अध्यक्ष की घोषणा हुई थी। एक वर्ष के अंदर ही पहले प्रदेश भाजयुमो अध्यक्ष शशि यादव को अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से हटाया गया।

एक वर्ष में दो मोर्चों के अध्यक्ष बदले

इसके बाद अब पूर्वांचल मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नीरज तीवारी को पद से हटाकर प्रदेश प्रवक्ता बना दिया गया। उनकी जगह मोर्चा में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे संतोष ओझा को अध्यक्ष की कुर्सी दी गई है। एक वर्ष में दो मोर्चों के अध्यक्ष बदलने से कई कार्यकर्ता प्रदेश नेतृत्व की कार्यप्रणाली पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं।

उनका कहना है कि पिछले वर्ष अगस्त में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने का दावा किया गया था, परंतु अब उन्हें हटाया जा रहा है। इससे स्पष्ट है कि पदाधिकारियों का चयन सही तरह से नहीं हुआ था।

मोर्चा की गतिविधियों को लेकर भी संतुष्ट नहीं था प्रदेश नेतृत्व

बताते हैं कि पिछले वर्ष दिसंबर में प्रदेश पूर्वांचल मोर्चा की टीम बनाते समय ही प्रदेश नेतृत्व के साथ तिवारी का विवाद शुरू हो गया था। उसके बाद भी कई मुद्दों पर तालमेल का अभाव था। लोकसभा चुनाव के बाद पूर्वांचल से सांसदों को सम्मानित करने के लिए उन्होंने प्रदेश नेतृत्व को विश्वास में लिए बिना एक कार्यक्रम आयोजित किया था। मोर्चा की गतिविधियों को लेकर भी प्रदेश नेतृत्व संतुष्ट नहीं था।

वहीं, इस कारण उन्हें और प्रभारी विजय भगत को पद से हटाया गया है। सह प्रभारी किशन शर्मा को भी पदमुक्त कर दिया गया। इन्हें भाजपा शाहदरा जिला का सह प्रभारी बनाया गया है, इसलिए पूर्वांचल मोर्चा की जिम्मेदारी लेने की बात कही जा रही है।

पार्टी के कई नेताओं को पूर्वांचल मोर्चा में बदलाव से गुटबाजी बढ़ने का डर है जिसका नुकसान विधानसभा चुनाव की तैयारी पर पड़ सकता है। दिल्ली में 30 प्रतिशत से अधिक पूर्वांचली मतदाता हैं, जिन्हें पार्टी के साथ जोड़ने की चुनौती है।

इस स्थिति को ध्यान में रखकर मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष बिपिन बिहारी सिंह को अध्यक्ष व मनीष सिंह को सह प्रभारी बनाया गया है। अब अध्यक्ष के साथ ही प्रभारी व सह प्रभारी के सामने सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को एकजुट कर पूर्वांचल के लोगों के बीच पार्टी की पकड़ मजबूत करने की है।

भाजपा ने जारी की प्रत्याशियों की लिस्ट, 30 उम्मीदवार ठोकेंगे ताल; रोचक होगा MCD वार्ड कमेटी का चुनाव

भाजपा ने दिल्ली नगर निगम की वार्ड समितियों के चुनाव के लिए 30 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में छह उम्मीदवारों के नाम घोषित नहीं किए गए हैं। सिविल लाइंस जोन से चेयरमैन के लिए अनिल त्यागी को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं केशवपुरम से योगेश वर्मा रोहिणी से रितु गोयल नरेला से पवन कुमार वेस्ट जोन से शशि तलवार को उम्मीदवार बनाया गया है।

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम की वार्ड समितियों के चुनाव की घोषणा के साथ ही विभिन्न दलों ने उम्मीदवारों के नाम पर मंथन शुरू कर दिया है। वहीं बीजेपी ने शुक्रवार को 30 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। वहीं इस लिस्ट में छह उम्मीदवारों के नाम घोषित नहीं किए गए हैं। सिविल लाइंस जोन से चेयरमैन के लिए अनिल त्यागी को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं केशवपुरम से योगेश वर्मा, रोहिणी से रितु गोयल, नरेला से पवन कुमार, वेस्ट जोन से शशि तलवार, सेंट्रल जोन से सुगधा, साउथ जोन से सुंदर सिंह, नजफगढ़ जोन से अमित खरकरी, शाहदरा (नॉर्थ) से प्रमोद गुप्ता और शाहदरा (साउथ) जोन से संदीप कपूर को उम्मीदवार बनाया गया है।

दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में 25,000 पद खाली, 2025 तक 20,000 लोगों को मिलेगा नियुक्ति पत्र

दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में 25000 पद खाली हैं और उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शुक्रवार को विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में 27 चिकित्सकों सहित दिल्ली सरकार और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) में नवनियुक्त 629 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली राज्य अधीनस्थ सेवा भर्ती बोर्ड (डीएसएसएसबी) द्वारा भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई गई है।

नई दिल्ली। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शुक्रवार को विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में 27 चिकित्सकों सहित दिल्ली सरकार और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) में नवनियुक्त 629 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली राज्य अधीनस्थ सेवा भर्ती बोर्ड (डीएसएसएसबी) द्वारा भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई गई है और हमारा लक्ष्य मार्च 2025 तक 20,000 और लोगों को नियुक्त करना है। उन्होंने बताया कि इस समय लगभग 18,000 रिक्तियां भर्ती के विभिन्न चरणों में हैं, जिन्हें जल्द पूरा किया जाएगा। अभी दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में करीब 25,000 पद खाली हैं। नई नियुक्तियों से रिक्तियों में कमी आएगी।

बैठक में राजस्व विभाग, एमसीडी, डीजेबी, बीएसईएस, डीयूएसआईबी, पीडब्ल्यूडी और दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हुए शामिल

सुषमा रानी

नई दिल्ली, दिल्ली के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने नीम वाला चौक नबी करीम से सदर थाना चौक तक निकलने वाली आगामी नायक समाज बाबा रामदेव शोभा यात्रा के सफल आयोजन के लिए विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मंत्री ने 05 सितंबर को निकाली जाने वाली बाबा रामदेव शोभा यात्रा के दौरान जरूरी और बुनियादी सेवाएं उपलब्ध करने की तैयारियों को लेकर समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों को साफ-सफाई, स्ट्रीट लाइट, जलापूर्ति और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इस बैठक में राजस्व विभाग, एमसीडी, डीजेबी, बीएसईएस, डीयूएसआईबी, पीडब्ल्यूडी और दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। शोभा यात्रा को संचालित करने वाली नायक समाज बाबा रामदेव शोभा यात्रा संस्था, दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारी ललित मलखट (अध्यक्ष), धर्मेंद्र महावर, दिलावर

मलखट, बिरजू नायक, अजय नायक, योगेन्द्र, सतपाल, अनिल, रवि पहलवान, गौरव, सुनील नायक, रवि वीडिया, विशाल, इंदर नायक, विशाल मलखट, सुरेश सिसोदिया, धरमचंद, सोनू नायक, रवि नायक, सत्यवान चौहान, सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।

यह शोभा यात्रा नीम वाला चौक नबी करीम, राम नगर, आराकाशा रोड, मोतिया खान, झंडेवालान रोड, ईदगाह रोड और सदर थाना चौक क्षेत्र होकर गुजरेगी। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने अधिकारियों को जिन इलाकों से होकर शोभा यात्रा गुजरेगी, वहां की सड़कों पर पर्याप्त स्वच्छता और साफ़-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। संबंधित अधिकारियों को इन क्षेत्रों में पेड़ों की शाखाओं की छंटाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और सड़कों की मरम्मत और रखरखाव को भी युद्ध स्तर पर करने के निर्देश दिए गए। मंत्री ने एमसीडी और पीडब्ल्यूडी को शोभा यात्रा मार्ग की सड़कों के साथ साथ गड्ढों और फुटपाथ की तत्काल मरम्मत करने के निर्देश दिए।

साथ ही मंत्री इमरान हुसैन ने डीजेबी और एमसीडी अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर ड्रेनेज रखरखाव कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया, ताकि जलभराव से बचा जा सके। खासकर बरसात के मौसम को देखते हुए क्षेत्र में गंदगी का निपटान सुनिश्चित किया जा सके। मंत्री ने डीजेबी को शोभा यात्रा के दौरान प्रमुख स्थानों पर पानी के टैंकरों की पर्याप्त व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया। मंत्री ने शोभा यात्रा के दिन यात्रा मार्ग में टॉयलेट ब्लॉक्स की व्यवस्था करने के लिए डीयूएसआईबी के अधिकारियों को निर्देश दिया। बीएसईएस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि एरिया में कोई भी बिजली का तार नीचे लटकता न पाया जाए। साथ ही क्षेत्र में बंद पड़ी स्ट्रीट व मास्ट लाइटों को भी बहाल किया जाए।

बैठक के दौरान मंत्री ने दिल्ली पुलिस और एरिया एसडीएम को आगामी नायक समाज बाबा रामदेव शोभा यात्रा के दौरान क्षेत्र में पुलिस कर्मियों, डीडीएमए की टीम और सिविल वालंटियर्स की तैनाती सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। दिल्ली पुलिस के ट्रैफिक विभाग को शोभा यात्रा के दौरान सुचारू यातायात सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए।

फिर एक और भारी बारिश जलभराव को रोकने के लिए कदम उठाने के जल मंत्री आतिशी के खोखले वादे को उजागर हुए -देवेंद्र यादव

सुषमा रानी

नई दिल्ली, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि जल भराव, सड़कों की बदहाल हालत, उफनते सीवर, गलियों और नालियों का बहता पानी, कूड़े के ढेर जैसी समस्याओं के कारण दिल्ली के लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर है क्योंकि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की प्रशासनिक नाकामियों के कारण अधिकारी करने को तैयार नही है। भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच चल रहे घमासान का खामियाजा दिल्ली की जनता को उठाना पड़ रहा है। पिछले 45 दिनों में जल भराव, नालों में डूबने और करंट लगने से हुई लगभग 37 मौतों के बावजूद केन्द्र और दिल्ली सरकार अपने राजनीतिक मंसूबों को पूरा करने में लगी है।

उन्होने कहा कि दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम की निष्क्रियता और पंगु प्रशासन के चलते जनता तक मौलिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। उन्हांने कहा कि दिल्ली की अधिकतर विधानसभाओं में सीवर का पानी गलियों में उपर तक बह रहा है और बारिश के कारण नालियां तालाब बन गई है। सौरभ भारद्वाज का निर्वाचन क्षेत्र ग्रेटर कैलाश तक लोगों को नरक झेलना पड़ रहा है। आप पार्टी व भाजपा के विधायको और जल मंत्री से राहत समाधान की आस में बैठे लोग अब समझ चुके है कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल को जेल से बाहर निकालने में लगी है वहीं भाजपा दिल्ली में 26 साल बाद सत्ता में हाने की नाकाम कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि जल मंत्री आतिशी के धौला कुआँ में जलभराव के दौरे के बाद, गुरुवार की भारी बारिश से फिर धौला कुंआ डूब गया, जिसको आतिशी ने कहा था सब ठीक होगा। उन्होंने कहा कि जिन विधानसभाओं में पिछले 1-2 वर्षों में सीवर लाईन डालने के बाद नीचे धंस गई है वहां दिल्ली जल बोर्ड सहित संबंधित विभाग के भ्रष्ट व लापरवाह अधिकारियों और ठेकेदारों की सीबीआई/विजिलेंस जांच कराई जाए।

यादव ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार का यह आलम है कि 2021-22 और 2022-23 की बैलेंस शीट ही गायब है, क्योंकि इन वर्षों में करोड़ों के भ्रष्टाचार किया गया है। उन्होंने कहा कि 2015-16 में लाभ कमाने वाला दिल्ली जल बोर्ड आज 73 हजार करोड़ का लोन और ब्याज की राशि का कर्जदार है। देवेन्द्र यादव ने कहा कि दिल्ली में अपना वजूद खो चुकी भाजपा और आम आदमी पार्टी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं।

यादव ने कहा कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए मंत्री गोपाल राय की 14 सूत्री शीतकालीन कार्य योजना एक और नौटंकी है, क्योंकि जिन 14 सूत्रों की बात की है उन पर सरकार प्रत्येक वर्ष वायु प्रदूषण से निपटने के लिए काम करती है परंतु सर्दियों में राजधानी में प्रदूषण के सभी रिकॉर्ड टूट जाते है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण वाहन प्रदूषण और राजधानी भर में टूटी सड़कों, कच्ची सड़कों और व्यस्त निर्माण गतिविधियों से निकलने वाली धूल है, इन प्रदूषणकारी एजेंटों की जांच करने के लिए कोई संबंधित एजेंसी नहीं है। उन्होंने कहा कि ताजा आंकड़ों के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण प्रत्येक दिल्लीवासी का जीवन सात वर्ष कम हो रहा है।

नोएडा की इस सोसायटी में पानी की भारी किल्लत झेल रहे 1600 परिवार, बाल्टी में पानी भर 19वीं मंजिल तक पहुंचा रहे

परिवहन विशेष न्यूज

ग्रेटर नोएडा की ला रेजीडेंसिया सोसायटी में पानी की मोटर खराब होने से 1600 परिवारों को पानी के लिए किल्लत झेलनी पड़ी है। बृहस्पतिवार शाम से शुक्रवार दोपहर तक मोटर ठीक नहीं हो सकी थी। सुबह टैंकरों से पानी की आपूर्ति की गई लेकिन लोगों को 19 मंजिला टावर में बाल्टी और बर्तन में पानी लेकर फ्लैट तक जाना पड़ा।

ग्रेटर नोएडा। सोसायटी में पानी की मोटर खराब होने से 1600 परिवार पानी के लिए परेशान रहे। बृहस्पतिवार की शाम खराब हुई मोटर शुक्रवार को दोपहर दो बजे तक ठीक हो सकी। सुबह टैंकरों से पानी की आपूर्ति हुई। लोग 19 मंजिला टावर में बाल्टी व बर्तन में पानी लेकर फ्लैट तक पहुंचे। आरोप है कि मोटर खराब होने की स्थिति में सोसायटी में पानी आपूर्ति के लिए वैकल्पिक इंतजाम नहीं हैं।

ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थिति ला रेजीडेंसिया सोसायटी में 1600 से अधिक परिवार रहते हैं। बृहस्पतिवार शाम ओवरहेड टैंक को भरने की मोटर खराब हो गई। ओवरहेड टैंकों का पानी खत्म होने के बाद एक-एक कर फ्लैटों में आपूर्ति ठप हो गई। शुक्रवार की सुबह लोग जागे तो दफ्तर जाने और बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी शुरू की। नल खोलकर देखे तो पानी नहीं आया।

प्रबंधन की ओर से सुबह टैंकर मंगाए गए

प्रबंधन से जानकारी करने पर पता चला कि मोटर खराब होने से ओवरहेड टैंक नहीं भर सके हैं, इससे फ्लैट में आपूर्ति बाधित हुई है। प्रबंधन की ओर से सुबह टैंकर मंगाए गए। लोग अपने घरों से बाल्टी और बर्तन लेकर पहुंचे और टैंकरों से पानी भरकर 19वीं मंजिल स्थित फ्लैट तक पहुंचे।

आरोप है कि सोसायटी में आए दिन पानी की दिक्कत होती है। पूर्व में मोटर खराब होने से पहले निवासी इस तरह की परेशानी झेल चुके हैं लेकिन प्रबंधन की ओर से कोई वैकल्पिक इंतजाम नहीं किए गए।

दफ्तर में लोग और स्कूल में बच्चे देरी से पहुंचे

सोसायटी में पानी नहीं आने से दफ्तर जा रहे लोग समय पर तैयार नहीं हो सके। निवासी अभिषेक चौहान ने बताया कि पानी की व्यवस्था करने में उनको काफी समय लगा। इसके बाद तैयार हुए और दफ्तर के लिए पहुंचे। दफ्तर में वह 45 से 50 मिनट की देरी से पहुंचे। वहीं, पानी नहीं आने की वजह से कई बच्चों की स्कूल बस छूट गई। इसके बाद अभिभावक बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए खुद पहुंचे।

मोटर खराब होने की नहीं दी सूचना

निवासी सुमिल जलोटा ने कहा कि बृहस्पतिवार की शाम खराब हुई पानी की मोटर की जानकारी निवासियों को नहीं दी गई। इस संबंध में लोगों को जानकारी दी जाती तो पानी का कम उपयोग करते और जरूरी कामकाज के लिए स्टोर करके रख सकते थे। मोटर खराब होने की स्थिति में प्रबंधन की ओर से पूर्व में भी कोई जानकारी नहीं दी गई।

"सोसायटी में पानी की मोटर खराब होने की जानकारी नहीं है। आपूर्ति के लिए वैकल्पिक इंतजाम भी हैं। अभी शहर से बाहर हूं। इस बारे में पता कर ही जानकारी दे सकूंगा। - कुलभूषण बजाज, निदेशक, ला रेजीडेंसिया"

टला नहीं है गाजियाबाद में बुलडोजर का खतरा, अब इस तारीख को अतिक्रमण मुक्त होगी 27 बीघा जमीन

परिवहन विशेष न्यूज

गाजियाबाद की नवीन फल और सब्जी मंडी में 2 सितंबर को बुलडोजर चलेगा। हालांकि दो प्लेटफॉर्म को लोगों ने खाली कर दिया था। 27 बीघा जमीन पर बने किसानों के चबूतरों पर लोगों ने कब्जा कर लिया था। किसानों को अपने ही चबूतरों पर सब्जी और फल बेचने नहीं दिया जा रहा था। दैनिक जागरण ने किसानों की पीड़ा को प्रमुखता से उठाया था।

गाजियाबाद। गाजियाबाद जिले के नवीन फल और सब्जी मंडी में अब 2 सितंबर को बुलडोजर चलेगा। हालांकि दो प्लेटफॉर्म को बिना बुलडोजर चलाए ही खाली करा लिया गया। अब पांच चबूतरे ऐसे हैं, जहां अभी भी अवैध कब्जा बना हुआ है। आज यूपी पुलिस की परीक्षा होने की वजह से मंडी के अधिकारियों को पुलिस बल नहीं मिला था, इस कारण बड़े पैमाने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं हुई थी।

बता दें, पुलिस ने यहां की 27 बीघे में बने फसल बेचने के चबूतरों को कब्जा मुक्त कराने के लिए 30 अगस्त की तारीख तय की थी। अरबों रुपये की भूमि पर बने किसानों के चबूतरों पर लोगों ने कब्जा कर लिया था। इस संबंध में नगर मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई के दौरान पर्याप्त पुलिस बल और पीएसी तैनात कराने के लिए पुलिस उपायुक्त ट्रांस हिंडन को पत्र लिखा था। मंडी में बागपत, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, गौतमबुद्ध नगर सहित अन्य जिलों से प्रतिदिन हजारों किसान व व्यापारी आते हैं।

चबूतरों पर दुकानदारों का कब्जा

किसानों के चबूतरों पर कुछ दुकानदारों ने कब्जा कर रखा है। अतिक्रमण करने वाले कुछ दुकानदारों पर लाइसेंस भी नहीं है। मंडी समिति पर ही किसानों के प्लेटफार्म पर कब्जा कराने का आरोप है। किसानों को चबूतरे पर सब्जी व फल बेचने नहीं दिया जाता है। मजबूरी में किसानों को सड़क पर फल व सब्जी बेचने पड़ रही है। दैनिक जागरण ने किसानों की पीड़ा पर प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। वहीं मंडी में हो रही अवैध अतिक्रमण पर लगातार खबरें प्रकाशित की।

किसानों के चबूतरों पर लोगों ने किया कब्जा

जांच में पाया गया कि मंडी में किसानों के चबूतरों पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। इसकी पूरी रिपोर्ट मुख्यालय भेजी गई। मंडी निदेशक के आदेश पर 30 अगस्त को 27 बीघे भूमि पर बने चबूतरों पर अवैध कब्जे को खाली कराया जाएगा।

नगर मजिस्ट्रेट ने पुलिस उपायुक्त ट्रांस हिंडन पत्र में लिखा है कि मंडी 11 नीलामी चबूतरे निर्मित हैं। इन पर कब्जा करने वालों की सूची बना ली गई है। 30 अगस्त को सुबह 11 बजे कब्जा हटवाया जाएगा। ऐसे में शांति भंग होने का अंदेशा है। इस संबंध में मंडी सचिव सुनील कुमार शर्मा को कई बार फोन और मैसेज किया गया लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया।

किसानों को मिलेगी राहत

किसानों के चबूतरों से कब्जा हटने के बाद उन्हें राहत मिलेगी। दर-दर की ठोकर खा रहे किसान अपने चबूतरों पर फसल बेच सकेंगे। काफी दिन से किसान चबूतरा खाली कराने की मांग कर रहे है। व्यापारी उनका समर्थन कर रहे थे।

नोएडा के बीचोंबीच बनेगा घने जंगल से घिरा 'ब्रह्मसरोवर', बोटिंग से लेकर एम्फीथियेटर तक होंगी कई सुविधाएं

नोएडा के सेक्टर-167 में घने जंगल से घिरा ब्रह्मसरोवर बनने जा रहा है। 29 हेक्टेयर में बनने वाले इस प्रोजेक्ट में 18 हेक्टेयर में घना जंगल 4 हेक्टेयर में सरोवर और 7 हेक्टेयर में मनोरंजन की सुविधा होगी। सरोवर में बोटिंग फूड कोर्ट वाकिंग ट्रैक और एम्फीथिएटर होगा। इसे पीपीपी मॉडल पर बनाया जाएगा और निर्माण लागत करीब 40 करोड़ रुपये होगी।

परिवहन विशेष न्यूज

नोएडा। नोएडा सेक्टर-167 में घने जंगल से घिरा ब्रह्मसरोवर बनेगा। उसमें बच्चों संग पूरा परिवार मस्ती कर सकेगा। नोएडा प्राधिकरण ने सलाहकार कंपनी का चयन कर लिया है। कंपनी इस सप्ताह प्राधिकरण के मुख्य कार्यपाल अधिकारी डॉ. लोकेश एम को अपना फाइनल प्रेजेंटेशन देगी। डिजाइन अप्रूव होने पर निर्माण के लिए टेंडर जारी किया जाएगा।

बढ़ाई जाएगी हरियाली

29 हेक्टेयर क्षेत्रफल में पूरा प्रोजेक्ट तैयार होगा। 18 हेक्टेयर में घना जंगल बनाया जाएगा। उसके बीच में चार हेक्टेयर में सरोवर और सात हेक्टेयर में रिक्रिएशनल एक्टिविटी होगी। उसमें फूड कोर्ट, वाकिंग ट्रैक, एम्फीथियेटर को शामिल किया जाएगा। यहां आने वाले लोगों को प्रकृति के पास होने का आनंद मिलेगा। इसका टिकट होगा या नहीं इस पर बाद में फैसला होगा।

सरोवर में कर सकेंगे बोटिंग

सरोवर के बीच में कमल के आकार का एक फाउंटेन लगाया जाएगा। बोटिंग की व्यवस्था की जाएगी। संचालक कंपनी बोटों की संख्या तय करेगी। सेक्टर-168 में के 150 एमएलडी के दो एसटीपी से सरोवर में शोधित पानी आएगा। इससे भूजल दोहन नहीं करना पड़ेगा। सीवर के पानी का सदुपयोग हो जाएगा।

पीपीपी मॉडल पर होगा तैयार

ब्रह्मसरोवर पब्लिक पार्टनर प्राइवेटशिप (पीपीपी) माडल पर बनाया जाएगा। डिजाइन होने के बाद जो कंपनी इसका निर्माण करेगा संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी उसी की होगी। राजस्व के लिए 30 और 70 प्रतिशत का रेशियो रखा जाएगा। यानी कुल आय का कंपनी को 30 फीसद नोएडा प्राधिकरण को देगी।

निर्माण लागत निकालने के लिए कंपनी यहां फूड कोर्ट, कैफेटेरिया, बोटिंग के अलावा विज्ञापन के राइटस ले सकती है। हालांकि उसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं करने दिया जा सकता। क्योंकि इसका लैंड यूज ग्रीन बेल्ट है।

40 करोड़ किए जाएंगे खर्च

डॉ. लोकेश एम के निर्देश पर सलाहकार कंपनी इस सरोवर का डिजाइन तैयार कर रही है। इसे तरह डिजाइन किया जा रहा है ताकि निर्माण में खर्च होने वाली लागत करीब 40 करोड़ के आसपास ही रहे। फाइनल एप्रूवल के बाद इसका निर्माण शुरू होगा। जिसे छह से आठ महीने में पूरा करना होगा।

उपचुनावों को लेकर CM योगी की रणनीति, विकास-रोजगार से सियासी खेल बदलने की तैयारी

अजय कुमार

मुख्यमंत्री योगी ने 15 अगस्त के बाद से प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा शुरू किया। अंबेडकर नगर से इस अभियान की शुरुआत हुई और इसके बाद अयोध्या, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़ और कानपुर जैसे महत्वपूर्ण जिलों का दौरा किया।

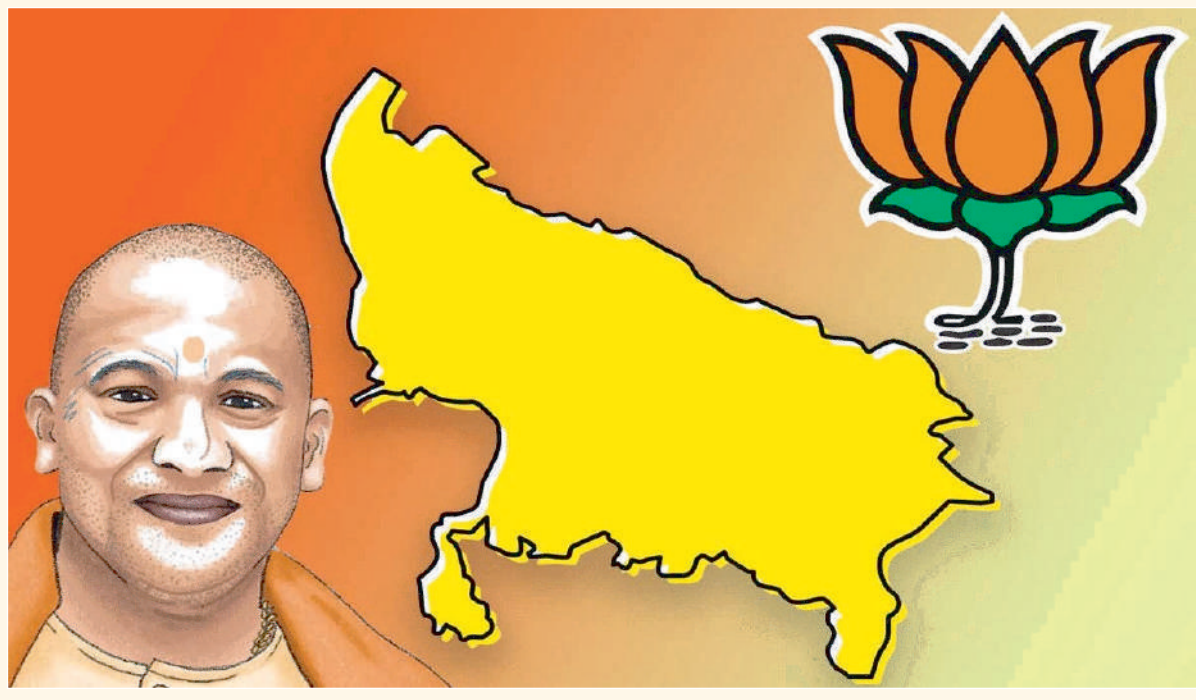

उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में जीत दर्ज करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद को पूरी तरह सक्रिय कर लिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को प्रदेश में बड़े झटके का सामना करना पड़ा था, जिससे अब ये उपचुनाव पार्टी के लिए बेहद अहम हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने 15 अगस्त के बाद से लगातार अलग-अलग जिलों का दौरा करके बीजेपी के लिए जीत की रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है। उन्होंने रोजगार मेलों के माध्यम से युवाओं को साधने और विकास परियोजनाओं के जरिए जनता की नाराजगी दूर करने का प्रयास किया है, ताकि बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया जा सके।

उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों में मीरापुर, गाजियाबाद, अलीगढ़ की खैर, करहल, कुंदरकी, फूलपुर, मिल्कीपुर, कटेहरी, मझवां और सीसामऊ जैसी सीटें शामिल हैं। इनमें से नौ सीटें 2024 के लोकसभा चुनाव में विधायकों के सांसद बनने के कारण खाली हुईं, जबकि सीसामऊ सीट समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के सजा होने के कारण खाली हुई है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इनमें से तीन सीटें जीती थीं, जबकि पांच सीटें समाजवादी पार्टी के पास थीं। शेष दो सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल और निषाद पार्टी के विधायक काबिज थे।

इसे भी पढ़ें: अयोध्या में 36 हजार से अधिक रोजगार के अवसर लेकर आईं 48 कंपनियां

बीजेपी के लिए ये उपचुनाव सिर्फ अपनी तीन सीटों को बचाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सपा के दबदबे वाली सीटों पर विजय हासिल करके 2024 के लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान की भरपाई करने का अवसर भी हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को छह सीटों पर सपा से कम वोट मिले थे, जिससे पार्टी की चिंता बढ़ गई थी। यही कारण है कि बीजेपी ने इन उपचुनावों को 2027 के विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल माना है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस चुनावी अभियान को प्राथमिकता दी है। उन्होंने खुद मैदान में उतरकर सियासी माहौल बनाने का मिशन शुरू कर दिया है।

मुख्यमंत्री योगी ने 15 अगस्त के बाद से प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा शुरू किया। अंबेडकर नगर से इस अभियान की शुरुआत हुई और इसके बाद अयोध्या, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़ और कानपुर जैसे महत्वपूर्ण जिलों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने रोजगार मेलों का आयोजन कर युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। हर जिले में पांच हजार से लेकर 17 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए, जिससे बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की गई है।

योगी आदित्यनाथ उपचुनाव वाले उन जिलों का दौरा कर रहे हैं, जहां रोजगार मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इन मेलों में युवाओं को मौके पर ही नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। इसके अलावा, योगी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी कर रहे हैं। उन्होंने लाभार्थीपरक योजनाओं के प्रमाण पत्र और छात्रों को टैबलेट्स वितरित किए हैं। इससे स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री योगी ने उपचुनाव वाली सीटों पर बीजेपी के लिए मजबूत आधार तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

बीजेपी की रणनीति में विकास, रोजगार और संवाद को मुख्य हथियार बनाया गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को युवाओं की बेरोजगारी को लेकर मिली नाराजगी का सामना करना पड़ा था, जो पार्टी की हार का एक प्रमुख कारण बना। इसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोजगार मेलों का आयोजन कर युवाओं को साधने की कोशिश की है। इन मेलों के माध्यम से युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे उनकी नाराजगी को कम किया जा सके।

मुख्यमंत्री योगी ने अपनी जनसभाओं में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखे हमले किए हैं। उन्होंने हिंदुत्व के एजेंडे को भी बढ़ावा देने का प्रयास किया है, ताकि बिखरे हुए हिंदू वोटों को एकजुट किया जा सके। योगी आदित्यनाथ ने हर जिले में उपचुनाव वाली सीटों के नेताओं के साथ बैठकें कीं और पार्टी की रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने न केवल राजनीतिक मोर्चे पर बल्कि शासन स्तर पर भी तैयारी की है, जिससे बीजेपी की जीत सुनिश्चित हो सके।

योगी आदित्यनाथ ने इन 10 सीटों पर जीत की जिम्मेदारी खुद संभाल ली है। उन्होंने दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष को भी इस चुनावी अभियान में शामिल किया है, जिनके जिम्मे दो-दो विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी है। साथ ही, मुख्यमंत्री ने अपनी कैबिनेट के मंत्रियों को भी मैदान में उतार दिया है, जो अपने-अपने क्षेत्रों में बीजेपी के लिए जीत सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं।

इन उपचुनावों में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती सपा की मजबूत सीटें हैं। करहल, कुंदरकी, कटेहरी, मिल्कीपुर और सीसामऊ जैसी सीटें बीजेपी के लिए कठिन मानी जा रही हैं। इसके अलावा, मझवां, मीरापुर और फूलपुर जैसी सीटें भी पार्टी के लिए आसान नहीं हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम पूरी तरह से इन सीटों पर फोकस कर रही है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस चुनावी अभियान को गंभीरता से लेते हुए पूरी ताकत झोंक दी है। रोजगार, विकास और संवाद के माध्यम से बीजेपी की रणनीति को मजबूत किया जा रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री योगी की यह मेहनत बीजेपी को उपचुनावों में कितनी सफलता दिला पाती है और पार्टी इस जंग को कैसे फतह करती है।

– :सौजन्य :–
ईवी ड्राइव द फ्यूचर
EV Drive the Future

रांची के लोग अब आराम से करें सफर, ऑटो और ई-रिक्शा की हड़ताल आज से खत्म

परिवहन विशेष न्यूज

झारखंड की राजधानी रांची में शुक्रवार यानी 30 अगस्त 2024 से एक बार फिर ऑटो और ई-रिक्शा सड़कों पर दौड़ते नजर आएंगे। दर्शन मार्ग निर्धारण और रोड परमिट को लेकर प्रशासन द्वारा लिए गए फैसले के विरोध में ऑटो और ई-रिक्शा चालक तीन दिनों से हड़ताल पर थे। गुरुवार यानी 29 अगस्त 2024 की देर शाम यह हड़ताल खत्म कर दी गई।

संभागीय आयुक्त ने यूनियन नेताओं के साथ बैठक की और निर्णय लिया गया कि प्रशासन ने जो भी निर्णय लिया था उसे वापस लिया जाता है और भविष्य में जो भी निर्णय लिया जाएगा वह यूनियन के साथ बैठक के बाद ही लिया जाएगा। इसके बाद ऑटो व ई-रिक्शा चालकों की मांग पूरी हो गई है। इसके बाद आज एक बार फिर लोगों के लिए ऑटो और ई-रिक्शा की सुविधा शुरू हो गई है।

ऑटो और ई-रिक्शा चालकों ने शहर की सड़कों पर चलने के लिए रूट परमिट जारी न करने, वाहनों पर मनमानी कार्रवाई और भारी जुर्माना लगाने के विरोध में परिवहन विभाग और प्रशासन के खिलाफ यह हड़ताल बुलाई थी। इस दौरान ऑटो और ई-रिक्शा एसोसिएशन के सदस्य हड़ताल के तहत सड़कों पर उतरे।

कर्नाटक में ईवी क्लस्टर के रूप में चिक्काबल्लापुर, बिदादी और हुबली-धारवाड़ को दिया गया अंतिम रूप

परिवहन विशेष न्यूज

संशोधित कर्नाटक इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023-28 के एक भाग के रूप में, वाणिज्य और उद्योग विभाग ने प्रस्तावित नए ईवी क्लस्टर के लिए स्थानों के रूप में चिक्काबल्लापुर और बिदादी और बेंगलुरु के पास हुबली-धारवाड़ को अंतिम रूप दिया है।

ईवी उद्योग की सिफारिशों के आधार पर इन क्लस्टरों को ईवी मॉडल सिटी भी कहा जाता है, जिन्हें कर्नाटक में ईवी को अपनाने को मजबूत करने के लिए विकसित किया जा रहा है। सरकार ने इन क्लस्टरों के लिए लगभग 800 एकड़ भूमि की पहचान की है।

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त गुंजन कृष्ण ने कहा, ₹हम चाहते हैं कि ईवी विनिर्माण और मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) (जो घटक बनाते हैं) एक ही स्थान पर हों। इसलिए हमने ये क्लस्टर बनाए हैं। निर्माता हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि पर आकर अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित कर सकते हैं।₹

अगर कंपनियां बिल्ड-टू-सूट सुविधा चाहती हैं, तो विभाग तीसरे पक्ष के साथ मिलकर इस पर काम करेगा और उसे उपलब्ध कराएगा। इन क्लस्टरों में ईवी उद्योग के लिए परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने की योजना है।

सुश्री कृष्णा ने कहा, ₹कुछ कंपनियों ने पहले ही चिक्काबल्लापुर जिले के गौरीबिदनूर क्लस्टर के रूप में काम करना शुरू कर दिया है।₹

सूत्रों के अनुसार कलबुर्गी, बेलगावी और मैसूरु जैसे अन्य स्थानों पर भी क्लस्टर स्थापित करने पर विचार किया गया था, लेकिन तीन स्थानों को आस-पास के जिलों में ईवी पैठ के आधार पर अंतिम रूप दिया गया है। सूत्र ने कहा, ₹हालांकि,

भविष्य में और अधिक क्लस्टर स्थापित करने की गुंजाइश है।"

कर्नाटक में ईवी इकोसिस्टम के निर्माण को बढ़ावा देने और एक स्थायी परिवहन ढांचा प्रदान करने के साथ-साथ, ईवी नीति का उद्देश्य इस क्षेत्र में 50,000 करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करना और एक लाख रोजगार के अवसर पैदा करना है।

कर्नाटक 2017 में ईवी नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य था। नई नीति की घोषणा तब की गई जब पहली नीति के पूरा होने की समयसीमा करीब आ गई।

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के साथ-साथ ऊर्जा विभाग जो ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए नोडल विभाग है, ने ईवी को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। हाल ही में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (बीईई) के आंकड़ों से पता चला है कि कर्नाटक में भारत में सबसे अधिक (5,765) सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन हैं। राज्य सरकार बिजली आपूर्ति कंपनियों के सहयोग से राज्य में 100 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 35 करोड़ रुपये का निवेश करने की भी योजना बना रही है।

रांची में 3000 ई-रिक्शा को सिटी पास देने का आश्वासन

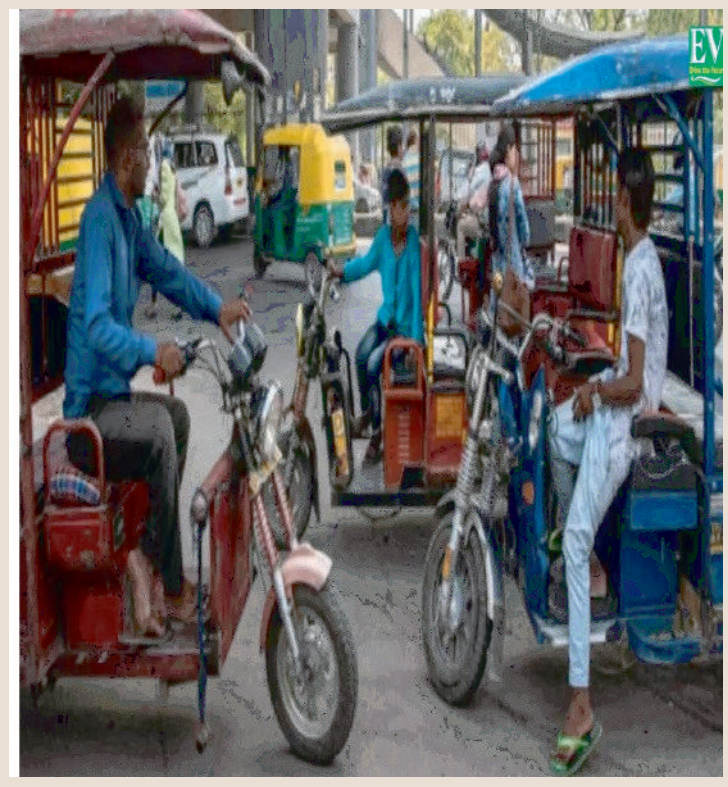

परिवहन विशेष न्यूज

रांची के कमिश्नर ने भरोसा दिलाया कि जनहित को ध्यान में रखकर ही कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा ऑटो और ई-रिक्शा को लेकर कोई भी अंतिम फैसला लेने से पहले यूनियन के साथ बैठक की जाएगी।

आयुक्त ने 3000 ई-रिक्शा को सिटी पास देने का आश्वासन दिया। साथ ही बताया गया कि कमिश्नर ने ऑटो परमिट को 17 रूटों में बांटने और नए ऑटो को परमिट देने पर रोक लगा दी है। जिसके बाद ऑटो और ई-रिक्शा चालकों ने हड़ताल खत्म करने का फैसला किया।

ऑटो और ई-रिक्शा चालकों द्वारा हड़ताल समाप्त करने की घोषणा के बाद तीनों ऑटो यूनियनों के पदाधिकारियों ने यात्रियों से माफी मांगी।

इथेनॉल से चलने वाले दोपहिया वाहनों का बड़े पैमाने पर किया जाएगा उत्पादन

परिवहन विशेष न्यूज

दोपहिया वाहन निर्माता देश में फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, कंपनियों ने ऐसे फ्लेक्स-फ्यूल दोपहिया वाहनों को बड़े पैमाने पर अपनाने की अनुमति देने के लिए नीति में बदलाव की भी मांग की है।

सूत्रों के हवाले से बताया गया कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ बैठक में कंपनियों ने कहा है कि वे ऐसे वाहन बनाने के लिए तैयार हैं जो 85 प्रतिशत इथेनॉल और उच्च इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर चल सकें। इस बीच टीवीएस मोटर, हीरो मोटोकॉर्प, होंडा और बजाज ने कहा कि वे कम से कम एक फ्लेक्स-फ्यूल दोपहिया वाहन का बड़े पैमाने पर उत्पादन करेंगे। इन्हें जनवरी 2025 में होने वाले ऑटो एक्सपो में प्रदर्शित किया जाएगा।

बैठक से जुड़े सूत्रों ने यह भी बताया कि वाहन निर्माता कंपनियों ने फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों के लिए ईंधन की कम और अलग कीमत रखने की भी मांग की है।

ऑटोमोबाइल उद्योग ने इन दोपहिया वाहनों पर 28 फीसदी की तुलना में 18 फीसदी की कम GST दर लागू करने का अनुरोध किया है। इसके अलावा उन्होंने देशभर में इथेनॉल-मिश्रित फ्यूल का विस्तार करने के लिए एक ठोस रोडमैप तैयार करने की आवश्यकता जताई है।

टाटा मोटर्स ने प्रवास 4.0 में नवीनतम वाणिज्यिक वाहनों का किया प्रदर्शन

परिवहन विशेष न्यूज

देश की सबसे बड़ी वाणिज्यिक वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने प्रवास 4.0 में दुनिया के सामने शून्य कार्बन उत्सर्जन वाले वाहनों की एक श्रृंखला का प्रदर्शन किया है। 29 से 21 अगस्त तक बेंगलुरु के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में सुरक्षित, स्मार्ट और टिकाऊ जन गतिशीलता समाधानों का प्रदर्शन किया गया। प्रवास 4.0 के पहले दिन टाटा मोटर्स ने बिल्कुल नई टाटा अल्ट्रा ईवी 7एम लॉन्च की। यह एक शून्य कार्बन उत्सर्जन वाली इंट्रा सिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा है, जिसे शहरों में घूमने-फिरने के लिए लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से डिज़ाइन किया गया है।

टाटा मोटर्स ने प्रवास 4.0 में सार्वजनिक परिवहन साधनों की विभिन्न श्रेणियों का प्रदर्शन किया है। इसमें टाटा मैग्ना ईवी, टाटा अल्ट्रा प्राइम सीएनजी, टाटा मैजिक बाय-फ्यूल, टाटा विंगर 9एस, टाटा सिटी राइड प्राइम और टाटा एलपीओ 1822 आदि शामिल हैं।

नई टाटा अल्ट्रा ईवी 7एम इलेक्ट्रिक बस में 21 यात्री आरामदायक तरीके से सफर कर सकते हैं। इस इलेक्ट्रिक बस को संकरी गलियों और भीड़भाड़ वाले शहर की सड़कों को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 213 किलोवॉट की इलेक्ट्रिक मोटर है और यह आईपी-67 रेटेड 200 केडब्ल्यूएच लिथियम-आयन बैटरी द्वारा संचालित है। अल्ट्रा ईवी 7एम एक बार चार्ज करने पर 160 किलोमीटर तक चल सकती है और दिलचस्प बात यह है कि इसे सिर्फ़ ढाई घंटे में पूरा चार्ज किया जा सकता है। टाटा अल्ट्रा ईवी 7एम में इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और ऑटोमैटिक पैसेंजर काउंटर सहित अन्य अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधाएँ हैं। टाटा अल्ट्रा ईवी 7एम इलेक्ट्रिक बस में रीजेनरेटिव ब्रेकिंग तकनीक शामिल है, जो इसकी दक्षता और रेंज को बढ़ाती है।

ग्राहक खुद चेक कर सकेंगे कारों की सेफ्टी रेटिंग और फीचर्स, भारत एनकैप ने लॉन्च किया क्यूआर कोड स्टिकर

परिवहन विशेष न्यूज

पिछले साल देश में शुरू हुए भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम यानी भारत एनकैप ने अब तक देश में बिकने वाली कुछ कारों का परीक्षण कर उन्हें सेफ्टी रेटिंग प्रदान की है। अब भारत एनकैप ने कारों के लिए सेफ्टी-रेटेड क्यूआर कोड स्टिकर लॉन्च करने की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य लोगों में वाहन सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ग्राहक स्टिकर पर मौजूद क्यूआर कोड को स्कैन करके वाहन के सेफ्टी फीचर्स के बारे में जान सकते हैं।

भारत एनकैप उन ऑटोमोबाइल निर्माताओं को क्यूआर कोड स्टिकर प्रदान करेगा, जिनके वाहनों का सेफ्टी प्रोग्राम के तहत क्रैश टेस्ट किया गया है। इन स्टिकर में निर्माता का नाम, वाहन या मॉडल का नाम, परीक्षण की तिथि और वयस्कों और बच्चों दोनों के लिए सेफ्टी स्टार रेटिंग शामिल होगी।

स्टिकर को स्कैन करके ग्राहकों को वाहन का विस्तृत विवरण पता चल जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल क्रैश टेस्ट पूरा करने वाले वाहनों में टाटा मोटर्स के टाटा सफारी, हैरियर, नेक्सन ईवी और पंच ईवी मॉडल शामिल हैं। इन मॉडलों को वयस्कों और बच्चों दोनों की सुरक्षा के लिए भारत एनकैप द्वारा 5-स्टार रेटिंग दी गई है।

पिछले साल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ग्लोबल एनकैप के साथ मिलकर भारत एनकैप सुरक्षा रेटिंग शुरू की थी। इस क्रैश-टेस्टिंग नीति के साथ, भारत वैश्विक स्तर पर इस तरह की सुरक्षा प्रणाली को अपनाने वाला पाँचवाँ देश बन गया। भारत एनकैप की घोषणा के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उल्लेख किया कि उन्हें इस स्वैच्छिक सुरक्षा योजना के तहत क्रैश टेस्ट के लिए पहले ही 30 से अधिक अनुरोध प्राप्त हो चुके हैं।

'अधिक सितारे, सुरक्षित कारें' का नारा भारत एनकैप के सभी नए वाहनों के लिए सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने और दुर्घटना दर को कम करने के मिशन को दर्शाता है। संगठन का यह भी मानना है कि यह पहल कार खरीदारों को वाहनों की सुरक्षा विशेषताओं को समझकर बेहतर जानकारी वाले विकल्प बनाने में सक्षम बनाएगी।

ममता का बंगाल और बेखौफ अपराधी

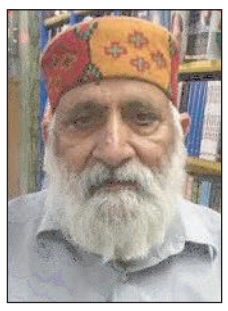

कुलदीप चंद अग्निहोत्री

दरअसल ममता जानती हैं कि बंगाल सरकार के सभी अवरोधों के चलते भी सीबीआई पर्दे के बाहर के और पर्दे के अंदर के अपराधियों को ही पकडऩे का प्रयास कर रही है। उसी से ध्यान बंटाने के लिए ममता अपने पुराने घिसे पिटे हथकंडे अपना रही हैं'

कोलकाता के आरजी कर राजकीय अस्पताल में एक डाक्टर के साथ बलात्कार के बाद उसकी अमानुषिक ढंग से हत्या कर दी गई। ऐसा जघन्य कार्य किसी भी प्रदेश में हो सकता है और इससे पहले हुआ भी होगा। लेकिन अन्य स्थानों पर हुए इस प्रकार के जघन्य अपराध और कोलकाता में हुए इस जघन्य अपराध के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। वह अंतर यह है कि ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल सरकार हर हालत में अपराधियों के साथ और उनको किसी भी तरह बचाने का प्रयास कर रही है। सरकार का काम अपराधियों को दंड देना और नागरिकों के जान और माल की रक्षा करना है। लेकिन पश्चिम बंगाल में सरकार अपराधियों के जान-माल की सुरक्षा के लिए तत्पर और महिला डाक्टर की जघन्य हत्या को आत्महत्या कह कर कूड़ेदान में डाल देने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, जब हत्या का हल्ला पडऩे लगा तो बंगाल सरकार को सबसे पहली यह चिंता हुई कि किसी तरह से घटना के स्थान से बलात्कार और हत्या के सबूतों को खत्म कर दिया जाए। सरकार इसके लिए बाकायदा किसी पुलिस वाले की ड्यूटी को लगा नहीं सकती थी। इस काम के लिए आनन फानन में लगभग सात हजार लोगों की भीड़ एकत्रित की गई जिसने अस्पताल पर धावा बोल दिया। पुलिस मूकदर्शक बन कर तमाशा देखती रही।

नाटक को विश्वसनीय बनाने के लिए इक्का दुक्का पुलिस के सिपाहियों पर भी हमला कर दिया गया ताकि नाटक में यह भाव आए कि पुलिस उपद्रवियों की भीड़ को रोकती रही, लेकिन स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर हो गई। इस तथाकथित नियंत्रण से बाहर हुई भीड़ ने उस सेमिनार हाल पर हमला कर दिया जहां उस अभागी डाक्टर की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। मेडिकल संस्थान ने तो उससे भी ज्यादा फुर्ती दिखाई। उसने उस सेमिनार हाल के कुछ हिस्से को गिरवाकर, उस हाल का नवनिर्माण अभियान चला दिया। लेकिन अब तक संस्थान के डाक्टर अपनी एक सहयोगी डाक्टर की इस अमानवीय हत्या के खिलाफ सडक़ों पर निकल चुके थे। अब तक कालेज के निदेशक डा. संदीप घोष पर चारों ओर से शक की सूईयां घूमने लगी थीं। भ्रष्टाचार से लेकर अस्पताल में लावारिस लाशों की बिक्री तक के चर्चे मीडिया में आने शुरू हो गए। यह सबको पहले से ही पता था कि घोष बाबू तृणमूल कांग्रेस में भी सक्रिय रहते ही हैं। लेकिन वही घोष बाबू अब तृणमूल कांग्रेस की सक्रियता के साथ साथ घटनास्थल सेमिनार हाल के कुछ हिस्से को तोडने के काम में भी सक्रिय हो रहे थे। तृणमूल और घोष बाबू दोनों समझ गए थे कि हालात जिस मोड़ पर पहुंच गए हैं, वहां उनका इस अस्पताल में रहना मुमकिन नहीं रहा। लेकिन ममता की ममता की दाद देनी होगी कि उन्होंने उसे तुरंत दूसरे मेडिकल कालेज का प्रिंसिपल बना दिया। एक रहस्य अभी तक नहीं सुलझ पाया कि आनन फानन में बलात्कार स्थल पर हजारों लोगों की भीड़ किसने और कैसे इकट्ठी की। इतना तो निश्चित है कि बलात्कार और हत्या का दोषी संजय राय अपने बलबूते इतने कम समय इतनी आक्रामक भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकता था। यकीनन इस भीड़ को बुलाने वाला गैंग कोई और था।

लेकिन यह गैंग अपराध के सभी सबूत खतरा लेकर भी क्यों मिटाना चाहता था? इस गैंग का संजय राय से क्या संबंध है? पुलिस ने किसके आदेश पर गैंग को बेखौफ होकर काम करने दिया?

यहां तक कि पुलिस पिटती रही लेकिन उसने प्रतिकार नहीं किया। पुलिस को यह आदेश प्रिंसिपल संदीप घोष तो नहीं दे सकता था। इतनी बड़ी उसकी औकात नहीं थी। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि भीड़ इकट्ठी करने वाला गैंग और प्रिंसिपल घोष बाबू दोनों ही किन्हीं कारणों से अपराधी संजय राय को बचाने का प्रयास कर रहे थे। किन्हीं बड़े कारणों या स्वार्थों के कारण ही ऐसा सम्भव है। इसलिए प्रश्न उठता है कि ऐसे कौन लोग हैं जिनके स्वार्थ संजय राय को बचाने में हो सकते हैं? संजय राय की गतिविधियां इस मेडिकल कालेज तक ही सीमित थीं। इसलिए जाहिर है कि वे स्वार्थ अस्पताल के अंदर ही हो सकते हैं। इस मोड़ पर प्रिंसिपल संदीप घोष शक के घेरे में आता है। लेकिन यहीं मामला समाप्त नहीं होता। ममता बनर्जी संदीप घोष को बचाने की कोशिश करती दिखाई दे रही हैं। वे उसे विवादग्रस्त अस्पताल से पदमुक्त होने पर तुरंत दूसरे विख्यात अस्पताल में नियुक्त कर देती हैं। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी बाकायदा सडक़ पर जुलूस निकालती हैं। यह जुलूस परोक्ष रूप से उनके खिलाफ था जो प्रिंसिपल को सजा देने और उसके घपलों और आचरण की जांच की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि महिला डाक्टर को जो बलात्कार और हत्या के रूप में सजा दी गई, उसके तार कहीं न कहीं अस्पताल के घोटालों से जुड़े हैं। यह प्रश्न सचमुच आश्चर्यचकित करता है कि बंगाल में जब भी कहीं महिलाओं से बलात्कार का मामला सामने आता है तो ममता बनर्जी की सरकार अपराधी के साथ खड़ी दिखाई देती है। संदेशखाली में भी ऐसा ही हुआ था और अब आरजी कर अस्पताल मामले में भी ऐसा ही हो रहा था। शायद यही कारण था कि कोलकाता उच्च न्यायालय और बाद में देश के उच्चतम न्यायालय ने पूरे घटनाक्रम का संज्ञान लेते हुए सबसे पहले जांच का सारा मामला ममता बनर्जी की पुलिस के हाथों से छीनकर सीबीआई को सौंप दिया।

केवल रिकार्ड के लिए, ममता बनर्जी ने सीबीआई को बंगाल में किसी आपराधिक मामले की जांच करने का अधिकार समाप्त कर रखा था। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इसके बावजूद यह मामला सीबीआई को जांच के लिए दिया। इतना ही नहीं, न्यायालय ने अस्पताल में सुरक्षा का जिम्मा भी बंगाल पुलिस के हाथ से लेकर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सौंप दिया। छात्रों ने महिला डाक्टर की हत्या के विरोध में शांति मार्च निकाला तो पुलिस ने उनकी जिस हिसाब से पिटाई की, वह अपने आप में कुख्यात मिसाल बन गई है। छात्राओं तक को सडक़ पर घसीट कर डंडों से पीटा गया। अंततः ममता ने घोषणा कर दी कि यदि अस्पताल के इस मामले को लेकर कोई बंगाल में आग लगाएगा, तो हम भी पूरे पूर्वोत्तर में आग लगा देंगे। अपराध के अधिकांश सबूत मिटाने के बाद ममता विधानसभा में बिल लाएंगी कि अपराधियों को दस दिन के अंदर फांसी पर लटका दिया जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वह महिलाओं की रक्षा के लिए युद्ध छेड़ देंगी। दरअसल ममता जानती हैं कि बंगाल सरकार के सभी अवरोधों के चलते भी सीबीआई पर्दे के बाहर के और पर्दे के अंदर के अपराधियों को ही पकडऩे का प्रयास कर रही है।

उसी से ध्यान बंटाने के लिए ममता अपने पुराने घिसे पिटे हथकंडे अपना रही है। लेकिन इस पूरे मामले में कपिल सिब्बल की बहादुरी की दाद देनी पड़ेगी। इस सबके बावजूद वे उच्चतम न्यायालय में बंगाल सरकार को बचाने के लिए जी-जान से जुटे हैं। वैसे तो यह उनका व्यवसाय है। पैसे लेकर अपने मुवक्किल को बचाना उनका काम है। लेकिन इधर खबर उड़ी थी कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जिसके वे प्रधान हैं, ने इस बलात्कार केस में अपने व्यक्तिगत विचारों को एसोसिएशन का प्रस्ताव कह कर प्रसारित कर दिया। तब बार के अनेक सदस्यों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की धमकी दी थी। न्यायालय में जब सोलिस्टर जनरल बलात्कार-हत्या मामले में बंगाल सरकार के रवैए की बात कर रहे थे, तो सिब्बल हंस रहे थे। अस्पताल के प्रिंसिपल की हरकतों और उन पर लगे आरोपों की गंभीरता को देखते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उनकी सदस्यता को निलंबित कर दिया है। कपिल सिब्बल का मामला भी क्या बार कौंसिल तक पहुंचेगा। सवाल यह भी है कि जिस बेटी की हत्या हुई, उसे इंसाफ मिल पाएगा?

'बहुत हो गया' के मायने

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बेटियों और महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर एक मार्मिक और अभूतपूर्व प्रतिक्रिया दी है। 'अभूतपूर्व' इसलिए है, क्योंकि देश के महामहिम अक्सर कोई सार्वजनिक बयान नहीं देते। राष्ट्रपति केंद्रीय कैबिनेट की सलाह पर ही काम करते हैं। संभवतः तीन पन्नों की यह प्रतिक्रिया सार्वजनिक करने से पूर्व राष्ट्रपति कार्यालय ने इसे प्रधानमंत्री दफ्तर भेजा हो और फिर कैबिनेट की संस्तुति के बाद यह पत्र देश के सामने आया हो! राष्ट्रपति ने अपनी मनःस्थिति बयां करते हुए अपनी निराशा, हताशा और भय का इजहार भी किया है। कल्पना की जा सकती है कि महिलाओं के खिलाफ बर्बर, पाशविक अपराधों ने राष्ट्रपति को कितना झकझोर दिया होगा कि उन्हें कहना पड़ा-'बस, अब बहुत हो गया।' एक राष्ट्र के तौर पर यह शर्मनाक और कलंकित स्थिति है कि राष्ट्रपति को लिखना पड़ा-'किंडरगार्टन की बच्चियों के साथ भी दरिंदगी की जा रही है। आज देश गुस्से में है और मैं भी'।' अब एक समाज के रूप में हम अपने आप से कुछ कठिन सवाल पूछें। राष्ट्रपति मुर्मू ने सवाल किया है कि 2012 में निर्भया कांड के बाद पूरा देश आंदोलित हो उठा था, लेकिन फिर लोगों ने यौन अपराधों को भुला दिया। क्या हमने यही सबक सीखा था? क्या हम 'सामूहिक स्मृतिलोप' के शिकार हैं? यह दुखद है और घिनौना भी है।' दरअसल राष्ट्रपति ने समाचार एजेंसी 'पीटीआई' के संपादकों से बातचीत की थी। बाद में उन्होंने तीन पन्नों का पत्र उन्हें लिखा। राष्ट्रपति ने उसमें उल्लेख किया है कि 'रक्षा बंधन' मनाने कुछ बच्चे 'राष्ट्रपति भवन' आए थे। उन्होंने 'निर्भया कांड' जैसी घटनाओं के मद्देनजर मुझसे सवाल पूछे। मैंने उन्हें 'मार्शल आर्ट्स' की ट्रेनिंग के बारे में बताया। हालांकि मैं जानती थी कि यह सुरक्षा की गारंटी नहीं है, लेकिन अब उन बच्चों के सवालों के जवाब समाज ही दे सकता है। किसी भी सभ्य समाज में बेटियों, महिलाओं के खिलाफ ऐसे जघन्य अपराध स्वीकार्य नहीं हैं, बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। हमें ईमानदार, निष्पक्ष आत्म-निरीक्षण की जरूरत है। अब हम न केवल इतिहास का सामना करें, बल्कि अपनी आत्मा के भीतर भी झांकें और इन अपराधों के कारणों की जांच करें। कोलकाता में एक तरफ प्रदर्शन हो रहे थे, दूसरी तरफ अपराधी भी घूम रहे थे। महिलाओं को कमतर आंकना भी घृणित मानसिकता है।

कोलकाता कांड ने राष्ट्रपति मुर्मू के मानस को झकझोरा होगा, लेकिन उन्होंने देश भर में बढ़ते बलात्कारों और हत्याओं के प्रति अपनी चिंता और सरोकार जताया है।

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विपक्ष के अन्य राजनीतिक दलों को इस पत्र से चिढऩा नहीं चाहिए अथवा 'राजनीतिक पत्र' नहीं आंकना चाहिए। हम अब एक परिपक्व गणतंत्र हैं, लिहाजा राष्ट्रपति के ऐसे सार्वजनिक कथन पर विचार करना चाहिए। चूंकि भारत के राष्ट्रपति ने पत्र लिख कर देश के हालात पर निराशा और पीड़ा जताई है, जाहिर है कि शेष विश्व भी यह पत्र पढ़ेगा और एकबारगी सोचेगा कि क्या भारत बलात्कारियों का देश है? भारत का अपमान होगा, उसकी छवि पर कालिख पुतेगी, क्योंकि राष्ट्रपति ने ही क्षोभ जताया है। हालात इस पराकाष्ठा तक पहुंच चुके हैं कि राष्ट्रपति को कहना पड़ा है-

'बस, अब बहुत हो गया।' राष्ट्रपति के इस कथन की अलग-अलग व्याख्याएं की जा सकती हैं। इसे बंगाल में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की पृष्ठभूमि माना जा सकता है, लेकिन किसी भी राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 356 चस्पां करने के संकेत तक भी सार्वजनिक नहीं किए हैं। ऐसा पत्र लिखना तो बहुत बड़ी बात है। यदि बंगाल में कोई कार्रवाई करनी है, तो उससे पहले मणिपुर पर भी सोचना पड़ेगा। उप्र, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र को भी नहीं छोड़ सकते, हालांकि इन राज्यों में ऐसी अराजकता नहीं फैली और न ही संवैधानिक नाकामी जैसी टिप्पणियां अदालत को करनी पड़ीं। मणिपुर की स्थिति वाकई विस्फोटक और नंगी रही है। वहां तो महिलाओं को वस्त्रहीन कर घुमाया गया है, बलात्कार की स्थितियां बाद में आती हैं। वहां तो शोषण और अत्याचार में महिलाएं ही महिलाओं के खिलाफ थीं। राष्ट्रपति को उस पर भी कुछ कहना चाहिए था। बहरहाल राष्ट्रपति ने अपने पत्र के जरिए कई बातें कही हैं। यदि हम वाकई सभ्य और शिक्षित, शालीन समाज हैं और हमारी आंखों में अब भी पानी शेष है, तो कमोबेश राष्ट्रपति के पत्र का कुछ पालन करना चाहिए।

राय

मुझे पुरस्कार मिल जाए तो'

प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद यदि मुझे पुरस्कार मिल जाए तो मेरे लिए अत्यंत हर्ष की बात होगी। परंतु यह हर्ष नितांत मेरा होगा। काश! इसमें मेरे समानधर्मा साहित्यकार और सगे-सम्बन्धी भी शामिल होते। वैसे साहित्य सेवा करते हुए मुझे तीस वर्ष का लम्बा समय बीत गया है, अतः कोई भी संस्था-अकादमी चाहे तो मुझे अपने पुरस्कार-सम्मान से नवाज सकती है। परंतु बात वही है कि मुझे पुरस्कार मिल जाए तो यह अनहोनी साहित्य जगत को पचाना मुश्किल हो जाएगा। बिना पुरस्कार प्राप्त किए ही जब मेरे समकालीन समानधर्मा साहित्यकार मुझसे दुःखी रहते हैं, तो यदि कोई लक्खी पुरस्कार मिल गया तो वह राशि उनके कष्टों के साथ-साथ मेरे व्यक्तिगत कष्टों में कई गुणा वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगी? एक बार मुझे एक स्थानीय संस्था ने मात्र माला पहनाकर तालियां बजवाई थी, उसमें भी मेरी खासी आलोचना हुई थी। लोगों ने इसे प्रायोजित कार्यक्रम बताया था। साहित्यकारों के घरों में कई दिनों तक मातमी धुनें बजती रही थीं। दरअसल मैं ठहरा अपनी धुन का साहित्यकार। थोड़ा रिजर्व नेचर का होने से समानधर्मा मुझे अहंकारी और घमंडी मानने लगे हैं। उन्होंने मुझे व्यावसायिक लेखक होने का तोहफा दिया है, जबकि मैं देश की उन्हीं पत्र-पत्रिकाओं में लिखता रहा हूं, जिनमें वे लोग लिखते हैं। फर्क इतना-सा है कि वे लिखने में थोड़ा शिथिल हैं, जबकि मैं गतिमान हूं। मेरा यही गतिमान होना ही मुझे अलग-थलग छोड़ देने का मुख्य कारण है। कोई मुझसे मिलना नहीं चाहता, बोलना नहीं चाहता और यहां तक कि वे मुझे अपने गुटों में घुसने नहीं देते।

इतनी डरावनी परिस्थितियों में यदि मुझे पुरस्कार मिल जाए तो असंख्य आपत्तियां और विपत्तियां उठ खड़ी हो सकती हैं। मुझे ही क्या, पुरस्कार देने वाली संस्था-अकादमी को भी नहीं बख्शा जाएगा। संस्था कार्यक्रम करेगी तो मेरे परिवारजनों के अलावा समारोहों में आएगा कौन? मुझे पता है वह समय मेरे लिए न सही, उस संस्था के लिए कितना अपमानपूर्ण होगा। साहित्य का पुरस्कार हो और उसमें साहित्यकार ही सम्मिलित न हों तो उस पुरस्कार की महत्ता क्या रह जाती है? कल्पना के घोड़े जब मेरे पुरस्कार लेने के मामले में दौड़ाता हूं तो अशुभ ज्यादा दिखाई देता है। मैं तो काली सूची में हूं ही, वह सम्मानीय संस्था भी इसी श्रेणी में घोषित की जा सकती है। इसीलिए ज्यादातर मुझे यही लगता रहता है कि मुझे साहित्य का पुरस्कार नहीं मिल सकता। इसीलिए मैंने पुरस्कार मिलने पर 'तो' लगाया है। वैसे लिखने-पढने और काम के आधार पर तो मुझे पुरस्कार न्यायोचित हो सकता है, लेकिन साहित्यगत में मेरी स्थिति सर्वथा भिन्न होने से पुरस्कार मिलना बहुत दुःखद घटना के रूप में भी लिया जा सकता है। जब मेरे लिखने-पढने से ही माहौल दूषित है तो पुरस्कार से मुझे नवाजा जाना मेरे अलावा किसे रास आएगा? एक बार मुझे पुरस्कृत करने की अफवाह मात्र उड़ी थी, उसी से उस संस्था के पास मेरे खिलाफ असंख्य आपत्तियां पहुंच गई थी। वास्तविकता का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इससे हुआ यह कि उस संस्था ने उस वर्ष से पुरस्कार देने की योजना ही आज तक स्थगित कर रखी है। अब संस्था दूसरे कार्यक्रम समारम्भ करने की योजना बना रही है, पुरस्कृत करने का घिनौना कार्यक्रम स्थायी रूप से बंद करने की सोच रही है।

दो परमाणु सम्पन्न देशों के बीच बेहतर संबंधों की जरूरत

अशरफ जहांगीर काजी

भारत -पाकिस्तान के रिश्ते इतने लंबे समय तक कभी इतने खराब नहीं रहे जितने आज हैं। एक ध्रुवीकृत लेकिन परस्पर निर्भर दुनिया में, जब प्रलय घड़ी आधी रात की ओर बढ़ रही है, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।

भारत -पाकिस्तान के रिश्ते इतने लंबे समय तक कभी इतने खराब नहीं रहे जितने आज हैं। एक ध्रुवीकृत लेकिन परस्पर निर्भर दुनिया में, जब प्रलय घड़ी आधी रात की ओर बढ़ रही है, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इन पड़ोसी परमाणु हथियार संपन्न देशों, जिनमें से एक की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है और दूसरे की पांचवीं सबसे बड़ी आबादी है, के बीच बेहतर संबंधों की जरूरत स्पष्ट होनी चाहिए।पाकिस्तान, दोनों देशों में से छोटा देश होने के नाते, कम से कम न्यूनतम आदान-प्रदान और सहयोग को बहाल करने और अधिक गंभीर मतभेदों को पारस्परिक रूप से स्वीकार्य तरीके से कैसे संबोधित किया जाए, इस पर अनौपचारिक या अप्रत्यक्ष चर्चा को बहाल करने में अपेक्षाकृत अधिक रुचि रखता है।

इसके विपरीत भारत ने पाकिस्तान के साथ किसी भी ठोस बातचीत में कमोबेश पूरी तरह से अरुचि दिखाई है। वह पाकिस्तान को एक असफल आतंकवादी देश के रूप में देखता है, जिसके पास बहुत कम विकल्प हैं जिनसे उसे केवल खुद को बचाने की जरूरत है। तदनुसार, वह ऐसे देश के साथ चर्चा में प्रवेश करने का कोई मतलब नहीं देखता। चर्चाएं, भले ही मैत्रीपूर्ण और विनम्र हों, एक-दूसरे के प्रति आधिकारिक, बल्कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण को दर्शाते हुए आरोप-प्रत्यारोप में बदल जाती हैं।

प्रश्न उठता है कि अधिकारियों, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, व्यापारियों, सभी प्रकार के पेशेवरों और विशेषज्ञों, सांस्कृतिक प्रतिनिधियों, छात्रों, पर्यटकों आदि सहित दोनों देशों के लोगों का एक व्यापक स्पैक्ट्रम एक-दूसरे के साथ अधिक से अधिक बातचीत कैसे बढ़ा सकता है जो समय के साथ एक-दूसरे के प्रति राजनीतिक दृष्टिकोण को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है? ऐसी प्रक्रिया के अभाव में, किसी भी मुद्दे पर चर्चा, चाहे वह कश्मीर हो, आतंकवाद हो, जल मुद्दे हों, अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार हो, व्यापार और निवेश बढ़ाना हो, विश्वास निर्माण के उपाय हों या पिछली वार्ताओं के एजेंडे में शामिल अन्य मुद्दे हों, निरर्थक हो जाती है। तो, दोनों देशों के बीच चर्चाएं अधिक फलदायी कैसे हो सकती हैं? 2 शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता है।

पहला, वार्ताकारों को एक ऐसा उद्देश्य सांझा करना चाहिए जिसे वे प्राप्त करने योग्य मानते हों। दूसरा, वार्ताकारों में आत्मनिरीक्षण करने और एक-दूसरे की ङ्क्षचताओं को दूर करने की आवश्यकता को स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए। यह आसान नहीं है। हाल ही में, जब एक भारतीय परिचित ने पूछा कि भारत-पाकिस्तान संबंध कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो मैंने सुझाव दिया कि पाकिस्तान खुद से पूछ सकता है कि वह कुछ भारतीय ङ्क्षचताओं को दूर करने के लिए क्या कर सकता है और भारत को भी इसी तरह खुद से पूछना चाहिए कि वह पाकिस्तानी चिंताओं को दूर करने के लिए क्या कर सकता है।

उन्होंने जवाब दिया कि भारत को पाकिस्तान से कहना चाहिए कि वह कश्मीर को भूल जाए, आतंकवाद को रोके, स्वीकार करे कि वह भारत के साथ अपनी प्रतिस्पर्धा हार चुका है। पाकिस्तान दक्षिण एशिया में भारत के प्रभुत्व को स्वीकार करे और तदनुसार अपने परमाणु शस्त्रागार को समाप्त कर दे। मैंने सुझाव दिया कि उन्होंने भारत के लक्ष्यों को स्पष्ट किया होगा, लेकिन पाकिस्तान की ङ्क्षचताओं को दूर करने की किसी भी इच्छा से प्रेरित नहीं दिखे। इसके बजाय, वह संभवतः एक समान प्रतिक्रिया प्राप्त करेंगे कि भारत आधिपत्य, हस्तक्षेप, हत्या, नरसंहार आदि की नीतियों से दूर रहे। इससे, निश्चित रूप से चर्चा समाप्त हो जाएगी।

तो, क्या हम इस तरह के बंजर आदान-प्रदान से आगे बढ़ सकते हैं? जहां तक कुछ आरोप उचित हो सकते हैं, उन्हें संबोधित किया जाना चाहिए, भले ही एकतरफा हों। क्या हम अपने देशों के बीच कुछ लंबित मुद्दों पर, जिनमें मुख्य ङ्क्षचताओं के मुद्दे भी शामिल हैं, एक ठोस बयान दे सकते हैं, साथ ही सहमत सिफारिशें भी कर सकते हैं, जिन्हें हम अपनी संबंधित सरकारों को विचार के लिए भेज सकते हैं? आपसी सहानुभूति को देखते हुए, न केवल व्यक्तिगत रूप से, बल्कि अलग-थलग पड़े पड़ोसी देशों के नागरिकों के रूप में भी, जो बहुत कुछ सांझा करते हैं, हम एक सांझा लेकिन अशांत इतिहास की बाधा को दूर करने की दिशा में प्रगति करना शुरू कर सकते हैं जिसने एक-दूसरे के प्रति हमारे दृष्टिकोण को 'अधिक आकार' दिया है।

इसके बजाय, हम एक-दूसरे के प्रति अपने दृष्टिकोण को बताने और व्यापक बनाने के लिए जो कुछ भी सांझा करते हैं, उसके लिए अधिक जगह दे सकते हैं। ऐसी बातचीत को धीरे-धीरे ट्रैक 2, ट्रैक 1.5 और आधिकारिक स्तरों तक बढ़ाने की आवश्यकता होगी। क्या हम इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि ऐसी प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए? यदि हां, तो क्या हम सार्क को पुनर्जीवित करने पर सहमत हो सकते हैं, जो वर्तमान में मरणासन्न है?

क्या हम विश्वास और सुरक्षा निर्माण उपायों को पुनर्जीवित कर सकते हैं जिन पर सहमति हो चुकी है, उन्हें लागू किया जा चुका है, और रद्द कर दिया गया है या अप्रचलित होने दिया गया है? क्या हम आज की परिस्थितियों में, जोखिमों के बावजूद, संबंधों में सुधार की संभावनाओं की गंभीरता से जांच करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति जुटा सकते हैं? या फिर क्या प्रतिपक्षी ताकतें बहुत मजबूत हैं और उन्हें मात देने की इच्छाशक्ति बहुत कमजोर है?

भारतीयों और पाकिस्तानियों की एक पूरी नई पीढ़ी को एक-दूसरे के बारे में और अधिक जानने की जरूरत है और वे एक-दूसरे के बारे में ऐसा क्यों सोचते और महसूस करते हैं। उन्हें पता चल सकता है कि वे जितना सोचते हैं, उससे कहीं अधिक बातों पर सहमत हैं। अगर ऐसा होता है, तो एक-दूसरे की चिंताओं को संबोधित करना आज की तुलना में बहुत कम मुश्किल हो सकता है। सभी प्रकार के आदान-प्रदान के साथ, आपसी समझ और आपसी लाभ के लिए लॉबी उभर सकती है, खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में। ऐसी लॉबी का अपने देशों की राजनीति और सरकारी निर्णय लेने में शिक्षाविदों, विशेषज्ञों और बुद्धिजीवियों की तुलना में कहीं अधिक प्रभाव होने की संभावना है।

सीमा पार व्यापार और अन्य आदान-प्रदान की क्षमता के अलावा, भारतीय और पाकिस्तानी, चाहे उनके राजनयिक संबंधों की स्थिति कैसी भी हो, एक-दूसरे के प्रति लोगों के रूप में उनकी कला, मनोरंजन और खेल में अडिग रुचि रखते हैं। दुर्भाग्य से, दोनों देशों के राजनेता और सरकारें, साथ ही विशिष्ट हित, कम उदार हैं और सुविधाकत्र्ता की तुलना में अधिक बाधाएं हैं। यह एक प्रारंभिक और समझने योग्य बात है। लेकिन सद्भावना, कल्पना और दृढ़ संकल्प वाले लोगों को बदलाव लाना शुरू करना होगा यदि भारत, पाकिस्तान और दक्षिण एशिया को संघर्ष प्रबंधन से विवाद समाधान की ओर बढऩा है और सामूहिक रूप से एक सुरक्षित, अधिक समृद्ध और खुशहाल दुनिया बनाने में मदद करना है।

खेल प्रतिभाएं

लोगों को खेलों के महत्व के बारे में जागरूक करने, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने, खेलों को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाकर फिट एवं स्वस्थ रहने के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। वास्तव में हॉकी के जादूगर के रूप में विख्यात मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर यह दिन मनाने का सबसे प्रमुख उद्देश्य अनुशासन, दृढ़ता, खिलाड़ी भावना, टीम वर्क इत्यादि खेलों के मूल्यों के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस का महत्व इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि इसी महीने कुछ भारतीय खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक में भारत की विजय पताका फहराकर लौटे हैं। यह गर्व का विषय है कि भारतीय खिलाड़ी अब क्रिकेट हो या निशानेबाजी, बैंडमिंटन हो या टेबल टेनिस, भारोत्तोलन हो या कुश्ती, हॉकी हो या भाला फैंक, तमाम खेल स्पर्धाओं में वैश्विक मंचों पर सफलता की इबारत लिख रहे हैं। पेरिस ओलंपिक में भले ही भारत के पदकों की संख्या इस बार पिछली बार से कम रही, लेकिन छह खिलाडियों ने पदक जीतकर और कुछ ने अपने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन कर देश को गौरवान्वित किया। मनु भाकर, सरबजोत सिंह, स्वप्निल कुसाले, नीरज चोपड़ा, अमन सहरावत तथा भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने तो ओलंपिक में पदक जीतकर देश में जश्न का माहौल बना दिया। ऐसे में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर ओलंपिक विजेताओं के प्रदर्शन पर चर्चा करना जरूरी है।

भारत को पेरिस ओलंपिक में सबसे पहली जीत दिलाई थी मनु भाकर ने, जिन्होंने ऐसा कमाल कर दिखाया था, जो 1904 के बाद से किसी भी ओलंपिक में कोई भी भारतीय खिलाड़ी नहीं कर पाया था। पहला कांस्य पदक जीतने के साथ ही वह ओलंपिक के इतिहास में भारत के लिए निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला शूटर बन गई और उस पदक के साथ ही मनु ने शूटिंग में भारत के पदक के 12 वर्ष के सूखे

को भी खत्म किया। ओलंपिक के 124 वर्ष के इतिहास में मनु से पहले भारत को शूटिंग में केवल 4 पदक ही नसीब हुए थे, जबकि भारत केवल पेरिस ओलंपिक में ही मनु के दो पदकों सहित कुल 3 पदक जीतने में सफल हुआ। निशानेबाज सरबजोत सिंह ने 30 जुलाई को मनु के साथ मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल का कांस्य पदक जीता था। सरबजोत के लिए यह पदक इसलिए बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि वह अपने पहले ओलंपिक में भाग ले रहे थे। सरबजोत ने इससे पहले 2023 में भोपाल में आयोजित हुए आईएसएसएफ विश्वकप में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता था तथा दक्षिण कोरिया में आयोजित हुई 15वीं एशियाई शूटिंग चौंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया था। एक अगस्त को पेरिस ओलंपिक में 50 मीटर राइफल श्री पोजीशन शूटिंग स्पर्धा में भारत के लिए तीसरा पदक जीता महाराष्ट्र के स्वप्निल कुसाले ने। ओलंपिक में भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी में मिली जीत के दृष्टिगत 8 अगस्त का दिन तो भारत के लिए ऐतिहासिक रहा, जब भारत हॉकी में लगातार दूसरे ओलंपिक में पदक जीतने में सफल हुआ। इसी के साथ नीरज चोपड़ा, विनेश फोगाट व कुछ अन्य खिलाडियों का प्रदर्शन भी उल्लेखनीय है। बहरहाल युवाओं में खेलों के प्रति जोश और जज्बा पैदा करने की सख्त जरूरत है।

क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम का आनंद लेना चाहते हैं? तो फ्रीडम सिप को चुनें

परिवहन विशेष न्यूज

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की फ्रीडम सिप एक बेहतरीन योजना है जो आपको SIP के माध्यम से वेल्थ बढ़ाने का मौका देती है। इसके अलावा इससे निवेशक को सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) के माध्यम से मासिक आय भी प्राप्त होती है। आप कुछ सरल तरीकों को अपनाकर इस योजना के माध्यम से वित्तीय स्वतंत्रता (फाइनेंशियल फ्रीडम) हासिल कर सकते हैं।

नई दिल्ली। अच्छे जीवन के बारे में आप दिन में कितनी बार सोचते हैं? एक ऐसा जीवन जहां आप काम और वित्तीय जरूरतों से बंधे नहीं हैं। आपको यह चुनने की स्वतंत्रता है कि आप अपना दिन कैसे बिताते हैं। चाहे बात घूमने की हो, बागवानी करने की, केवल पढ़ने की, या स्लो लाइफ जीने की, ये सपने आपके हैं। अगर आप इन्हें पूरा करना चाहते हैं, तो इसका एक तरीका है—वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनिए। ICICI Prudential Mutual Funds के Freedom SIP को चुनकर आप वित्तीय रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं। इसे ICICI प्रूडेंशियल Freedom SIP के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में:

Freedom SIP एक बेहतरीन योजना है जो आपको SIP के माध्यम से वेल्थ बढ़ाने का मौका देती है। इसके अलावा, इससे निवेशक को Systematic Withdrawal Plan (SWP) के माध्यम से मासिक आय भी प्राप्त होती है। आप कुछ सरल तरीकों को अपनाकर इस योजना के माध्यम से वित्तीय स्वतंत्रता (Financial Independence) हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले, अपनी SIP अमाउंट चुनें। फिर अपनी अवधि और स्कीम का चयन करें, जिसमें सॉर्स स्कीम शामिल हो—यह वह योजना है जहां आप अपनी SIP शुरू करेंगे। साथ ही, टारगेट स्कीम चुनें, जो आपकी SWP से जुड़ी योजना होगी। अंत में, अपनी SWP अमाउंट तय करें। जब तक टारगेट स्कीम में यूनिट्स उपलब्ध रहेंगी या म्यूचुअल फंड द्वारा बताई गई तिथि तक, आपको मासिक SWP अमाउंट मिलती रहेगी। यह वही मासिक आय है जो आपके आदर्श जीवन के लिए आवश्यक हो सकती है।

Freedom SIP एक शानदार गोल-बेस्ड इन्वेस्टिंग सॉल्यूशन है, जो आपको लॉन्ग-टर्म निवेश की आदत डालने में मदद करता है। साथ ही, यह आपको अपनी पसंद की अवधि चुनने की आजादी भी देता है। इसके अतिरिक्त, यह योजना आपको आपकी वित्तीय आवश्यकताओं और जोखिम उठाने की क्षमता के अनुरूप, सॉर्स और टारगेट स्कीम की एक विस्तृत श्रृंखला से चुनने में सक्षम बनाती है, जिससे आपकी वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा आसान और प्रभावी हो जाती है।

यह सलाह दी जाती है कि आप सही म्यूचुअल फंड स्कीम चुनें और जितनी जल्दी हो सके अपना Freedom SIP शुरू करें, क्योंकि जितने लंबे समय तक आप निवेशित रहेंगे, आपका मासिक SWP भुगतान उतना ही बड़ा होगा। Freedom SIP के साथ, वित्तीय स्वतंत्रता अब आपके करीब है!

बैंकिंग सिस्टम में घट रहा कैश, क्या ये चिंता की बात है?

बैंकिंग सिस्टम में नकदी 2.86 लाख करोड़ रुपये के उच्चस्तर से घटकर 28 अगस्त को 0.95 लाख करोड़ रह गई है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे महीने के दौरान नकदी में गिरावट जारी रही। महीने की शुरुआत यानी दो अगस्त को बैंकिंग प्रणाली में नकदी 2.56 लाख करोड़ रुपये थी जो 28 अगस्त को 0.95 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर आ गई।

नई दिल्ली। भारत के बैंकिंग सिस्टम की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। लोन ग्रोथ के मुकाबले बैंकों की डिपॉजिट ग्रोथ लगातार कम हो रही रही है। अब देश के बैंकिंग सिस्टम में नकदी में भी बड़ी गिरावट आई है। यह 2.86 लाख करोड़ रुपये के उच्चस्तर से घटकर 28 अगस्त को 0.95 लाख करोड़ रह गई है।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस पूरे महीने के दौरान नकदी में गिरावट जारी रही। महीने की शुरुआत यानी दो अगस्त को बैंकिंग प्रणाली में नकदी 2.56 लाख करोड़ रुपये थी, जो 16 अगस्त को घटकर 1.55 लाख करोड़ रुपये और 28 अगस्त को 0.95 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर आ गई।

वित्त मंत्री की अपील के बाद भी गिरावट

नकदी में यह गिरावट वित्त मंत्री और आरबीआई गवर्नर द्वारा बैंकों से सिस्टम में नकदी बढ़ाने के उपाय की बार-बार अपील के बावजूद आई है। नकदी का लगातार घटता स्तर चिंता का विषय है और इसका आर्थिक गतिविधियों पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है।

महीने की शुरुआत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के साथ समीक्षा बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि ऋण वृद्धि में तेजी आई है, लेकिन इसे स्थायी रूप से वित्तपोषित करने के लिए जमा राशि बढ़ानी होगी। सीतारमण ने बैंकों को अपने ग्राहकों के साथ बेहतर संबंध बनाने की भी सलाह दी थी।

डिपॉजिट ग्रोथ पर भी जताई थी चिंता

पिछले दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों में घटते डिपॉजिट पर चिंता जताई थी। उन्होंने आरबीआई निदेशक मंडल के साथ मीटिंग के बाद कहा था कि बैंकों को कुछ इनोवेटिव और आकर्षक पोर्टफोलियो लाने के बारे में सोचना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बैंकों में पैसे जमा करें। अभी लोगों के पास अधिक रिटर्न पाने के लिए बैंकों से अच्छे कई विकल्प हैं। इनमें शेयर बाजार भी एक है। यही वजह है कि शेयर मार्केट में रिटेल इन्वेस्टमेंट तेजी से बढ़ा है।'

किसानों की बल्ले-बल्ले: इस बार धान खरीदारी का टूटेगा रिकॉर्ड! सरकार ने तय किया बड़ा टारगेट

केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने राज्यों के साथ बैठक के बाद इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 485 लाख टन धान का लक्ष्य रखा है। बैठक में मानसूनी बारिश की स्थिति खरीफ फसलों के उत्पादन का अनुमान एवं राज्यों की तैयारी पर चर्चा की गई। केंद्र ने खरीफ मौसम के लिए सामान्य ग्रेड धान के एमएसपी में 117 रुपये की वृद्धि की है।

नई दिल्ली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सप्लाई चेन और अन्य सुधारों पर विचार करते हुए केंद्र सरकार इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 485 लाख टन धान की खरीद करेगी। साथ ही 19 लाख टन श्रीअन्न (मोटे अनाज) की भी खरीद करेगी। पिछले खरीफ मौसम (2023-24) में 463 लाख टन धान की खरीदारी हुई थी। इस बार 22 लाख टन ज्यादा धान खरीदा जाएगा।

केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने शुक्रवार को राज्यों के साथ बैठक के बाद यह लक्ष्य तय किया है। बैठक में मानसूनी बारिश की स्थिति, खरीफ फसलों के उत्पादन का अनुमान एवं राज्यों की तैयारी पर चर्चा की गई।

केंद्र ने खरीफ मौसम के लिए 'सामान्य' ग्रेड धान के एमएसपी में 117 रुपये की वृद्धि की है। किसान 2,300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से सामान्य धान एमएसपी पर बेच सकते हैं। वहीं, ए ग्रेड धान का एमएसपी 2,320 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की सचिव निधि खरे ने राज्यों के खाद्य सचिवों एवं खाद्य निगम (एफसीआई) के साथ खरीफ विपणन सत्र (2024-25) के लिए फसलों की खरीदारी से संबंधित व्यवस्थाओं पर विमर्श किया। पिछली बार सिर्फ 6.60 लाख टन मोटे अनाज की ही खरीदारी हो पाई थी।

मजबूत वैश्विक रुख से सेंसेक्स-निफ्टी नए शिखर पर, 116 शेयरों के नहीं बदले भाव

परिवहन विशेष न्यूज

Share Market ग्लोबल मार्केट सितंबर में ब्याज दरों में कटौती और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के आश्वसन से प्रभावित होने के लिए दिखेगा। वहीं आज सेंसेक्स-निफ्टी नए शिखर पर पहुंच गया। पिछले नौ दिनों की लगातार तेजी में 1941.09 अंक बढ़ा सेंसेक्स और निफ्टी 12 सत्रों की लगातार तेजी में 1096.9 अंक चढ़ा है। आइए इसके बारे में विस्तार में जानते हैं।

नई दिल्ली। वैश्विक बाजारों में मजबूती के रुख और विदेशी कोषों की लिवाली के चलते शुक्रवार को प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी अपने नए सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गए। सूचकांक में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाली कंपनियों भारती एयरटेल, आइसीआइसीआइ बैंक और इन्फोसिस के शेयरों में खरीदारी से भी बाजार धारणा को बल मिला।

116 शेयरों के दाम में नहीं हुआ बदलाव

लगातार 9वें कारोबारी सत्र में तेजी के साथ, 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 231.16 अंक चढ़कर 82,365.77 के सर्वकालिक उच्चस्तर पर बंद हुआ। दिन के कारोबार में यह 502.42 अंक उछलकर 82,637.03 अंक के नए रिकार्ड उच्चस्तर पर पहुंच गया था।

नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी 83.95 अंक बढ़कर 25,235.90 अंक के नए सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गया। निफ्टी लगातार 12वें दिन तेजी के साथ बंद हुआ। दिन के कारोबार में यह 116.4 अंक बढ़कर 25,268.35 अंक के नए उच्चस्तर पर पहुंचा था। बीएसई पर 2,228 शेयरों में तेजी आई, जबकि 1,701 में गिरावट आई और 116 शेयरों के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ।

"वैश्विक बाजार सितंबर में ब्याज दरों में कटौती के अमेरिकी फेडरल रिजर्व के आश्वसन से प्रभावित हैं। अमेरिकी और भारतीय बाजारों ने हाल के उच्चस्तर को फिर से हासिल कर लिया है।"

इतना बढ़ा सेंसेक्स और निफ्टी

पिछले नौ दिनों की लगातार तेजी में 1,941.09 अंक बढ़ा सेंसेक्स और निफ्टी 12 सत्रों की लगातार तेजी में 1,096.9 अंक चढ़ा है।

आठ बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर जुलाई में सुस्त, घटकर हुई 6.1 प्रतिशत

चालू वित्त वर्ष के पहले चार माह (अप्रैल-जुलाई) में बुनियादी उद्योगों का उत्पादन 6.1 प्रतिशत बढ़ा है इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 6.6 प्रतिशत की दर से बढ़ा था। आठ बुनियादी उद्योगों का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में भारांश 40.27 प्रतिशत का है। IIP समग्र औद्योगिक वृद्धि का मापक है। जुलाई में कच्चे तेल का उत्पादन 2.9 प्रतिशत और प्राकृतिक गैस का उत्पादन 1.3 प्रतिशत घटा।

नई दिल्ली। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में गिरावट के कारण जुलाई में आठ प्रमुख बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर घटकर 6.1 प्रतिशत रह गई है। हालांकि, यह मासिक आधार पर जून के 5.1 प्रतिशत से ज्यादा रही है। जुलाई, 2023 में आठ बुनियादी उद्योगों- कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली क्षेत्र का उत्पादन 8.5 प्रतिशत की दर से बढ़ा था।

चालू वित्त वर्ष के पहले चार माह (अप्रैल-जुलाई) में बुनियादी उद्योगों का उत्पादन 6.1 प्रतिशत बढ़ा है, जबकि इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 6.6 प्रतिशत की दर से बढ़ा था। आठ बुनियादी उद्योगों का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आइआइपी) में भारांश 40.27 प्रतिशत का है। आइआइपी समग्र औद्योगिक वृद्धि का मापक है। जुलाई में कच्चे तेल का उत्पादन 2.9 प्रतिशत और प्राकृतिक गैस का उत्पादन 1.3 प्रतिशत घटा।

विदेशी मुद्रा भंडार 681 अरब डॉलर के नए उच्चस्तर पर

23 अगस्त को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 7.023 अरब डॉलर बढ़कर 681.688 अरब डॉलर के नए उच्चस्तर पर पहुंच गया। इससे पिछले सप्ताह विदेशी मुद्रा भंडार 4.546 अरब डॉलर बढ़कर 674.664 अरब डॉलर हो गया था। विदेशी मुद्रा भंडार का पिछला सर्वकालिक उच्चस्तर दो अगस्त को समाप्त सप्ताह में 674.919 अरब डॉलर दर्ज किया गया था।

आरबीआई द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार 23 अगस्त को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 5.983 अरब डॉलर बढ़कर 597.552 अरब डॉलर हो गईं। समीक्षाधीन सप्ताह में स्वर्ण भंडार 89.3 करोड़ डॉलर बढ़कर 60.997 अरब डालर हो गया। शीर्ष बैंक ने कहा कि विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) 11.8 करोड़ डॉलर बढ़कर 18.459 अरब डालर हो गए। शीर्ष बैंक के आंकड़ों से पता चलता है कि आइएमएफ के साथ भारत की आरक्षित स्थिति तीन करोड़ डालर बढ़कर 4.68 करोड़ डॉलर हो गई।

पहली तिमाही में 6.7 फीसदी रही भारत की जीडीपी ग्रोथ, 15 महीनों में सबसे कम

जीडीपी को सबसे अधिक चोट एग्रीकल्चर और माइनिंग सेक्टर से लगी। अप्रैल-जून 2025 के बीच कृषि क्षेत्र की ग्रोथ घटकर 2 फीसदी आ गई। एक साल पहले यह 3.7 फीसदी थी। हालांकि, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री ने अच्छी ग्रोथ दर्ज की।

नई दिल्ली। भारत की अर्थव्यवस्था अब सुस्त पड़ रही है। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ घटकर 6.7 फीसदी पर गई। यह पिछली पांच तिमाहियों ने 15 महीनों में सबसे कम है। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.8 फीसदी की दर से बढ़ी थी। जीडीपी ग्रोथ का पिछला निचला स्तर जनवरी-मार्च 2023 में 6.2 प्रतिशत था। जीडीपी को सबसे अधिक चोट एग्रीकल्चर और माइनिंग सेक्टर से लगी। अप्रैल-जून 2025 के बीच कृषि क्षेत्र की ग्रोथ घटकर 2 फीसदी आ गई। एक साल पहले यह 3.7 फीसदी थी। हालांकि, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री ने अच्छी ग्रोथ दर्ज की। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर की ग्रोथ जून तिमाही में 10.4 फीसदी रही है, जो एक साल पहले 3.2 फीसदी थी।

भारत अब भी चीन से ज्यादा तेज

इस सुस्ती के बावजूद भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है, क्योंकि चीन की जीडीपी अप्रैल-जून के दौरान सिर्फ 4.7 फीसदी की दर से बढ़ी। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग की वृद्धि एक साल पहले की अवधि के 5 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 7 प्रतिशत हो गई।

यूरोप में मुद्रास्फीति घटकर 2.2 प्रतिशत पर आई, ब्याज दरों में कटौती का रास्ता साफ

यूरोस्टैट के शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार अगस्त का आंकड़ा जुलाई के 2.6 प्रतिशत से कम है। अगस्त में ऊर्जा की कीमतों में तीन प्रतिशत की गिरावट आई जिससे समग्र आंकड़े कम करने में मदद मिली जबकि यूरो क्षेत्र की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी में मुद्रास्फीति घटकर दो प्रतिशत पर आ गई है।

नई दिल्ली। यूरो का उपयोग करने वाले यूरोपीय संघ (ईयू) के 20 देशों में मुद्रास्फीति अगस्त में तेजी से घटकर 2.2 प्रतिशत पर आ गई है। इससे यूरोपीय केंद्रीय बैंक (ईसीबी) के लिए ब्याज दरों में कटौती का रास्ता खुल गया है। ईसीबी और अमेरिकी फेडरल रिजर्व वृद्धि और नौकरियों को समर्थन देने के लिए कर्ज की लागत कम करने की तैयारी कर रहे हैं।

ईयू की सांख्यिकी एजेंसी 'यूरोस्टैट' के शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, अगस्त का आंकड़ा जुलाई के 2.6 प्रतिशत से कम है। अगस्त में ऊर्जा की कीमतों में तीन प्रतिशत की गिरावट आई, जिससे समग्र आंकड़े कम करने में मदद मिली, जबकि यूरो क्षेत्र की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी में मुद्रास्फीति घटकर दो प्रतिशत पर आ गई है। मासिक आंकड़ा अब ईसीबी के दो प्रतिशत के लक्ष्य के करीब है, जो अर्थव्यवस्था के लिए सबसे अच्छा माना जाने वाला स्तर है।

ईसीबी को यूरोपीय संघ की स्थापना करने वाली संधि के तहत स्थिर कीमतें बनाए रखने का काम सौंपा गया है। यूरोपीय संघ के सभी 27 देश यूरो का उपयोग नहीं करते हैं। अर्थशास्त्रियों को उम्मीद है कि ईसीबी 12 सितंबर की बैठक में अपनी प्रमुख ब्याज दर को 3.75 प्रतिशत से 0.25 प्रतिशत तक घटा सकता है, जबकि फेडरल रिजर्व द्वारा भी 17-18 सितंबर की अपनी नीतिगत बैठक में ब्याज दर में कटौती की उम्मीद है। अभी अमेरिका में नीतिगत दर 5.25-5.50 प्रतिशत के 23 साल के उच्चतम स्तर पर है।

इस साल आर्टिफिशियल बारिश कराने की तैयारी में दिल्ली सरकार , केंद्र से मांगी इजाजत

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि वो आर्टिफिशयल बारिश की परमिशन के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को चिट्ठी लिखेंगे. एक्सपर्ट्स के साथ मीटिंग के बाद उन्होंने ये बात कही. दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिये दिल्ली सरकार के विंटर एक्शन प्लान को लेकर सचिवालय में बड़ी बैठक हुई. इसमें आर्टिफिशियल बारिश को लेकर भी चर्चा हुई. दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने विंटर एक्शन प्लान को लेकर दोपहर 12 बजे सभी अधिकारियों और पर्यावरण से जुड़े विशेषज्ञों की मीटिंग बुलाई थी. इस बैठक में एक्सपर्ट से उन सुझावों पर चर्चा हुई जिसके ज़रिये प्रदूषण की समस्या को कम किया जा सके.

आर्टिफिशियल बारिश को लेकर केंद्र को लिखेंगे चिट्ठी-गोपाल राय

बैठक के बाद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इन सुझाव के बारे में जानकारी देते हुये कहा कि आर्टिफ़िशियल बारिश को लेकर पिछले साल हमने एक कोशिश की थी. आज सुझाव आए हैं कि इसे लेकर पहले से ही काम शुरू हो. यानि जितनी भी फार्मिलिटी है वो समय रहते पूरी कर ली जाये ताकि ज़रूरत पड़ने पर आर्टिफिशियल बारिश करायी जा सके. उन्होंने कहा, ₹इसको लेकर कल मैं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को चिट्ठी लिखूंगा ताकि पहले से ही इसके लिये परमिशन आदि को लेकर चर्चा हो सके जिसमें आईआईटी के एक्सपर्ट्स और अधिकारी भी साथ रहे."

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2016 में 110 दिन ऐसे थे जब एक्यूआई अच्छी कैटेगरी में थी. पिछले साल यह बढ़कर 206 दिन हो गये जब एक्यूआई बेहतर स्थिति में रही. यह हमारे लिये बड़ी उपलब्धि है. ख़ासकर इस दौर में जबकि दिल्ली की जनसंख्या बढ़ी है, कंस्ट्रकशन बढ़ा है, गाड़ियां बढ़ी हैं, प्रोडक्शन बढ़ा है. गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के निवासियों, पड़ोसी राज्यों और केंद्र के सहयोग से भी हम ये कामयाबी हासिल करने में सफल रहे.

पिछले साल 14 बिंदुओं के आधार पर बना था विंटर एक्शन प्लान

गोपाल राय ने कहा कि हर साल अक्टूबर महीने के बाद दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ना शुरू होता है, जो जनवरी तक रहता है. इसके लिए सरकार हर साल विंटर एक्शन प्लान तैयार करती है. इस साल के लिये भी इस पर काम करना शुरू कर दिया है. आज इसके लिए विशेषज्ञों को बुलाया गया था. इसमें महत्वपूर्ण विभागों के लोग भी शामिल हुए. सभी सुझावों को हम विंटर एक्शन प्लान में शामिल करेंगे. पिछले साल 14 बिंदुओं के आधार पर विंटर एक्शन प्लान बनाया गया था.

गोपाल राय ने कहा कि आज मिले सुझावों पर संबंधित विभागों को कार्योजना बनाने को कहा गया है, 5 सितंबर को सभी विभागों की ज्वाइंट बैठक भी होगी. उनकी कार्योजना को पर्यावरण विभाग समायोजित करेगा और उसे जनता के सामने रखा जाएगा.

वर्क फ्रॉम होम को और प्रमोट करने की ज़रूरत- मंत्री

कुछ सुझावों के बार में बताते हुये गोपाल राय ने

कहा कि ज़ीरो कार्बन को लेकर आज पूरी दुनिया में कैम्पेन चल रहा है. आज इसे लेकर भी सुझाव आया. लोगों के बिहैवियर पैटर्न को बदलने के लिए कैम्पेन को भी इस बार एक्शन प्लान में शामिल करने का सुझाव आया है. उन्होंने कहा कि एक्सपर्ट्स का सुझाव आया है कि वर्क फ्रॉम होम को और प्रमोट करने की ज़रूरत है, ख़ासकर प्राइवेट दफ्तरों के लिए ये बेहतर विकल्प हो सकता है. मैक्सिको में एक एक्सपेरिमेंट हुआ है वॉलियंटियरली व्हीकल रिस्ट्रिक्शन का. सुझाव आया है कि ऑड-ईवन की जगह इसका प्रयोग किया जाए.

मंत्री गोपाल ने कहा कि उसके ज़रिये लोगों को इस बात के लिये प्ररित किया जायेगा कि वो खुद से ही कुछ समय के लिये अपनी गाड़ियों को सड़कों पर नही निकले ताकी ईंधन से होने वाली प्रदूषण को कुछ हद तक कम किया जा सके. हालांकि इसको लेकर ऑड-ईवन जैसी कोई ज़रूरी प्रतिबंध नहीं होगा. ये लोगों के ऊपर होगा कि वो बढ़ते प्रदूषण को देखते हुये सड़कों पर गाड़ी लेकर ना निकले और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करे.

'ऑफिस टाइम को बदलने का भी सुझाव'

कुछ और सुझावों के बारे में बताते हुये मंत्री गोपाल राय ने कहा कि एक्सपर्ट से ऑफिस टाइम को बदलने का भी सुझाव आया है. क्योंकि ऑफिस जाने आने वाले सभी लोग एक समय पर ही आते जाते हैं और इससे जाम बढ़ता है और सड़कों पर गाड़ियाँ ज़्यादा समय तक रहती है जिससे प्रदूषण बढ़ता है. इसके अलावा गोपाल राय ने कहा कि सर्दियों में जो गार्ड होते है वो ठंड से बचने के लिये अंगीठी जलाते हैं. सुझाव आया है कि सीएसआर के ज़रिए उन्हें हीटर मुहैया कराया जाए. इसके साथ ही प्रदूषण को लेकर जो हॉट स्पॉट्स है. उन जगहों पर टार्गेटेड व्हीकल ट्रैफ़िक कम करने का भी सुझाव आया है.

हे द्रौपदी !

तुम्हें तो कोई छू भी नहीं सकता।
फिर भी तुम्हें डर है,
उन हैवानों का, उन नर पिशाचों का।
जिनसे बेटियों की आबरू,
अंदर तक काँप गई है।
आपने कहा ₹अब बहुत हो चुका।₹
क्या इन दरिंदों से लड़ पाओगी?
न्याय के झंडे को ऊंचा कर पाओगी।
चिंता बड़ी गहरी है। अफ़सोस...
लेकिन उस पर कोई प्रहरी नहीं है।
डर समझ में आता है।
मुझे तो हर बार,
एक सपोला नजर आता है।
जो झुंड बनाकर आता है,
कोमल शरीर का जर्रा-जर्रा
अंदर तक काँप जाता है?
बस, कुचलना है उसका फन,
आत्मा भी पूछ हिलाते फिरेगी।
इन सपोलों में ₹डर₹ बिठाना है,
वासना की आग को
हमेशा के लिए मिटाना हैं।
हे द्रौपदी!
बस एक बार मन में ठान लेना,
फिर कभी कोई सपोला,
तुम्हें छू भी नहीं सकता।

मैं, तुम और कौन ?

अरे मैं रूठा, तुम भी रूठ गई,
फिर हमें मनाएगा कौन ?
आज दरार पड़ी है,
कल को ये खाई होगी,
फिर उसे भरेगा कौन ?
आज मैं चुप, तुम भी चुप,
इस चुप्पी को फिर तोड़ेगा कौन ?
अगर छोटी-सी बात को,
प्रिये लगा लोगे दिल से
फ़रि ये रिश्ता निभाएगा कौन ?
यारा दुखी मैं भी और तू भी
सच, एक दूजे को
ढाढ़स बंधवाएगा कौन ?
कल को ज़ब हम बिछड़ गए,
तो सोचो हाथ बढ़ाएगा कौन ?
न मैं राजी, न तुम राजी,
फिर हममे से माफ़ करने का
ये बड़प्पन दिखाएगा कौन ?
ज़ब कभी मुझ पर टूटेगा,
मुसीबतों का पहाड़
तब मुझे धैर्य बंधायेगा कौन ?
चुभेंगे ज़ब यादों के नश्तर,
मेरे आँसू पोछेगा कौन ?
एक ज़िन्दिगी मिली हैं
तुम्हें भी और मुझे भी,
एक डोर से बांधेगा कौन ?
तेरा अहम, मेरा भी अहम,
बता इसे छुड़वाएगा कौन ?
ऐ जान-ए-जिगर संगदिल,
आजा मेरे गले से लग जा
कि कल पछताएगा कौन ?

सीरवी समाज पारसीगुटा बडेर नवनिर्वाचित तीनों कमेटी का भव्य सम्मान समारोह आयोजित

श्री आईजी सेवा संघ में सीरवी समाज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के सम्मान समारोह कार्यक्रम में नवनिर्वाचित अध्यक्ष मोहनलाल हाम्बड़, उपाध्यक्ष रमेश पंवार, सचिव नारायणलाल काग, कोषाध्यक्ष खंगारसिंह लचेटा, शिक्षा समिति अध्यक्ष लाबुराम पंवार, उपाध्यक्ष वोराराम भायल, सहसचिव रमेश परिहार का सम्मानकर उपस्थित श्री आईजी संघ अध्यक्ष भगाराम मुलेवा,कोरमुला बडेर अध्यक्ष कालुराम काग, सचिव डायाराम लचेटा,अ.भा. सीरवी महासभा अध्यक्ष हरजीराम काग, पारसीगुटा बडेर पूर्व अध्यक्ष भुराराम चोयल,आईजी गौशाला अध्यक्ष मंगलाराम पंवार,सचिव हुक्माराम सनपुरा, भंवरलाल मुलेव,शमशाबाद बडेर अध्यक्ष आशाराम गेहलोत, सचिव भोलाराम पंवार,रामलाल बर्फा, पारसमल शर्मा, मोतीलाल काग, गणेशराम बर्फा, कालुराम चिंतल, नारायणलाल सीन्दड़ा, बाबूलाल मुलेवा,ओंकारराम हाम्बड , कानाराम सुचित्रा, किशनलाल पंवार, चेनाराम परिहार,व समाज बन्धु।

सहयोग सेवार्थ फाउन्डेशन भीलवाडा के भीख नही ,किताब दो अभियान "के तहत गंगरार के चंदनपुरा स्कूल में स्टेशनरी और LED टी .वी .भेट की

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

भीलवाड़ा सहयोग सेवार्थ फाउन्डेशन के सहयोग से प्राथमिक विद्यालय चंदनपुरा, ग्राम पंचायत मंडफिया, पंचायत समिति गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ में समारोह आयोजित किया गया सहयोग सेवार्थ फाउन्डेशन भीलवाडा के सचिव गोपाल विजयवर्गीय ने बताया कि भीख नहीं किताब दो अभियान के तहत कैलाश चंद वैष्णव प्रधानाचार्य व सहयोग सेवार्थ फाउन्डेशन भीलवाडा की प्रेरणा से₹भीख नही किताब दो अभियान ₹के तहत विद्यालय में कार्यरत शिक्षक यशपाल सिंह शक्तावत , सूरज कुमार द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय चंदनपुरा को एक 32₹LED टी वी भेट की गई।LED TV के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के विधार्थी देश और दुनिया की डिजिटल तकनीक, पढ़ाई के नए तरीके, आदि से रूबरू हो सकेंगे।आंगनबाड़ी और विद्यालय मे अध्यनरत सभी विधार्थियों को सहयोग सेवार्थ फाउन्डेशन भीलवाडा के सहयोग से नोटबुक, पैन अतिथियो द्वारा वितरीत की गई । इस अवसर पर मुख्य अतिथि कैलाश चंद वैष्णव प्रधानाचार्य मंडफिया, अशोक कोचिटा प्रधानाध्यापक माताजी का खेड़ा, भैरू लाल गंधर्व पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष राष्ट्रीय शिक्षक संघ गंगरार , ज्ञानेश्वर शुक्ल प्रधानाध्यापक फलोदी एवम धर्मचंद आचार्य प्रबोधक व सहयोग सेवार्थ फाउन्डेशन भीलवाडा के सदस्य उपस्थित थे। अतिथियों ने जवासिया स्कूल के जरूरतमंद विधार्थियों के लिए नोटबुक कोपिया भैरू लाल गन्धर्व को भी भेट की और अतिथियों ने ज्ञानेश्वर शुक्ल प्रधानाध्यापक के सेवानिवृत होने पर साफा,माला और उपरना पहनाकर इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर चंदनपुरा स्कूल के स्टॉफ , अभिभावक, ग्रामीणजन और विधार्थी उपस्थित थे।।

अमेठी और रायबरेली: गांधी परिवार की विरासत और नए मोर्चे - आशीष कुमार

अमेठी और रायबरेली—भारतीय राजनीति की ये दो सीटें एक ऐसा इतिहास समेटे हुए हैं, जिसे अनदेखा करना असंभव है। एक समय था जब इन सीटों से देश के प्रधानमंत्री चुनाव लड़ते थे, और ये सीटें कांग्रेस के किले के रूप में जानी जाती थीं। इंदिरा गांधी रायबरेली से, जबकि राजीव गांधी अमेठी से अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की थी। यह कहना गलत नहीं होगा कि इन सीटों का महत्व केवल चुनावी राजनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यहां से देश की राजनीति की दिशा और दशा भी तय होती रही है।

समय के साथ परिस्थितियाँ बदलीं और अब अमेठी की सीट पर गांधी परिवार के लोग नही है। 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराकर अमेठी की सीट पर कब्जा कर लिया। कांग्रेस के लिए यह एक बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 2024 के लोकसभा चुनाव में, कांग्रेस ने किशोरी लाल शर्मा को अमेठी से उम्मीदवार बनाया, जो चुनाव में स्मृति ईरानी को हार थमाया । इस जीत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार किया और पार्टी को उम्मीद दी कि वह अमेठी में अपनी पुरानी जमीन वापस पा सकती है।

राहुल गांधी का नया सफर

राहुल गांधी ने अपनी राजनीतिक यात्रा को एक नया आयाम दिया जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा का उद्देश्य न केवल पार्टी को संगठित करना था, बल्कि देशभर में जनता के बीच अपनी छवि को भी मजबूत करना था। राहुल गांधी ने इस यात्रा के माध्यम से उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जो आम जनता के दिल से जुड़े हुए थे—बेरोजगारी, महंगाई, किसान समस्याएं, और महिला सुरक्षा। इस यात्रा ने उन्हें जनता के करीब लाने का एक महत्वपूर्ण अवसर दिया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया उत्साह पैदा किया।

इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने पैदल चलकर विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने जनता से सीधा संवाद स्थापित किया, जिससे न केवल उन्हें जनता के मुद्दों को गहराई से समझने का मौका मिला, बल्कि उन्होंने अपनी छवि को भी एक जिम्मेदार और संवेदनशील नेता के रूप में स्थापित किया। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी ने एक बार फिर कांग्रेस को एकजुट किया और पार्टी में नई जान फूंक दी।

इतिहास की ओर एक नजर

अमेठी और रायबरेली का इतिहास गांधी परिवार के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। 1952 और 1957 में इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी ने रायबरेली से चुनाव जीता था। 1971 में इंदिरा गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ा और जीता, लेकिन राज नारायण ने चुनाव परिणाम को चुनौती दी और यह मामला अदालत तक पहुंचा। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनावी अनियमितताओं का दोषी पाया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा। इस फैसले के बाद देश में आपातकाल लागू कर दिया गया, जिसने भारतीय लोकतंत्र को एक नया मोड़ दिया।

1977 के चुनाव में जनता का गुस्सा आपातकाल के खिलाफ फूट पड़ा और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव हार गईं, जो कि एक ऐतिहासिक घटना थी। इसके बाद, 1980 में इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी ने अपनी सीटें बचाईं। लेकिन संजय गांधी की अचानक मौत के बाद, अमेठी की सीट खाली हो गई और राजीव गांधी को राजनीति में उतारा गया। राजीव गांधी ने अमेठी से चुनाव जीतकर अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की और कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

वर्तमान और भविष्य की रणनीति

राहुल गांधी ने अमेठी सीट हारने के बाद भी हार नहीं मानी। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से अपनी राजनीतिक यात्रा को एक नई दिशा दी। इस यात्रा के दौरान उन्होंने विभिन्न राज्यों का दौरा किया और जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित किया। उन्होंने अपनी पार्टी को फिर से संगठित किया और कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने एक नई ऊर्जा और उत्साह प्राप्त किया है, जो आगामी चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है।

2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने रणनीतिक रूप से फैसला किया कि राहुल गांधी को अमेठी से नहीं लड़ाया जाए, जिससे राहुल बनाम स्मृति ईरानी की टक्कर से बचा जा सके। इसके बजाय, राहुल गांधी केरल के वायनाड के साथ रायबरेली से भी चुनाव लड़े। क्योंकि सोनिया गांधी राज्य सभा जाने का फैसला कर चुकी थी । राहुल गांधी ने वायनाड से चुनाव जीतकर रायबरेली की सीट को प्राथमिकता दी और वायनाड की सीट छोड़ दी। इस फैसले के बाद कांग्रेस ने तय किया कि वायनाड सीट से प्रियंका गांधी आगामी उपचुनाव में चुनाव लड़ेंगी। यह निर्णय कांग्रेस के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि प्रियंका गांधी का राजनीति में सक्रिय होना कांग्रेस के लिए एक नए युग की शुरुआत हो सकती है।

प्रियंका गांधी की राजनीति में भूमिका

प्रियंका गांधी का राजनीति में प्रवेश कांग्रेस के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। उनका चुनावी मैदान में उतरना न केवल पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है, बल्कि जनता के बीच भी उनकी लोकप्रियता बढ़ाने में मदद करेगा। प्रियंका गांधी ने पहले भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जिम्मेदारी संभाली है और पार्टी को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत की है। अब वायनाड से उपचुनाव लड़ने का उनका फैसला पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, जिससे कांग्रेस को एक नई दिशा मिल सकती है।

प्रियंका गांधी का राजनीतिक कद उनके परिवार की विरासत से जुड़ा हुआ है, और यह देखना दिलचस्प होगा कि वे इस विरासत को कैसे आगे बढ़ाती हैं। वायनाड से चुनाव लड़ना उनके राजनीतिक करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है, जो उनके नेतृत्व कौशल को और निखारने में मदद करेगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता और समर्थक भी इस फैसले से उत्साहित हैं और उन्हें प्रियंका गांधी से काफी उम्मीदें हैं।

राहुल गांधी की राजनीति में नई दिशा

राहुल गांधी ने अपने नेतृत्व में कांग्रेस को नई दिशा दी है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी छवि एक मजबूत और जुझारू नेता के रूप में उभरी है। उन्होंने पार्टी के भीतर संगठनात्मक ढांचे को मजबूत किया और कार्यकर्ताओं के बीच विश्वास बहाल किया। राहुल गांधी का नेतृत्व न केवल कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि देश की राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है।

राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने कई मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याओं, और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत की है। उनके इस नेतृत्व ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी नई ऊर्जा दी है, जिससे वे आगामी चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित हुए हैं।

राहुल गांधी ने हमेशा जनता के मुद्दों को प्राथमिकता दी है और यही कारण है कि उनकी राजनीति जनता के दिलों में जगह बना रही है। उनकी भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस को एक नई पहचान दी है और आने वाले समय में यह देखना होगा कि यह पहचान कैसे कांग्रेस के भविष्य को आकार देती है।

समाप्ति और निष्कर्ष

अमेठी और रायबरेली की सीटें सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र नहीं हैं, बल्कि ये भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो देश की राजनीति की दिशा तय करती हैं। इन सीटों का इतिहास गांधी परिवार के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है, और वर्तमान में भी इनका महत्व कम नहीं हुआ है। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा और नेतृत्व के माध्यम से इन सीटों की राजनीति को एक नई दिशा दी है।

राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जनता के बीच एक मजबूत छवि बनाई है, और उनके नेतृत्व ने कांग्रेस को एक नई दिशा दी है। कांग्रेस का भविष्य अब इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपने नेतृत्व में कैसे सुधार करती है और आगामी चुनावों में कैसे प्रदर्शन करती है। प्रियंका गांधी का वायनाड से चुनाव लड़ना और राहुल गांधी का रायबरेली की सीट को चुनना कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो पार्टी के भविष्य को आकार दे सकता है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095 . newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी .आर .बी . एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। **RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023**